Table within the period prescribed in sub-section (2) of section 16 of the said Act. [*Placed in Library. See.* No. LT- 432/69].

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 :—

(1) The Cotton Textiles (Control) Amendment Order, 1969, published in Notification No. S.O. 2588 in Gazette of India dated the 5th July, 1959

(2) The Textiles (Production by Knitting, Embroidery, Lece making and Printing Machines) Control Amenment Order, 1959, published in Notificatlon No. S O. 2539 in Gazettee of India daded the 5th July, 1969

(3) The Cotton Control (Amendment) Order, 1969, published in Notification No. S.O. 2590 in Gazette of India dated the 5ih July, 1969

(4) The Textiles (Production by Power-loom) Control Amendment Order, 1959. published in Notificatin No. S.O. 2591 in Gazette of India dated the 5th July, 1969

(5) The Cotton Textiles (Export Control) Amendment Order, 1969, published in Notification No. S.O, 2592 in Gazette of India dated the 5th July, 1969.

(6) The Cotton Textiles (Control of Movement) Amendment Order, 1969 publisned in Notification No. S.O 2593 in Gazette of India dated the 5th July, 1969. [*Placed in Library.See* No. LT—1433/69.]

———

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESULTIONS

Fifty-first Report

SHRI S.M. SOLANKI : (Nagaur) I beg to present the fifty-first Report of the Committee on Private Members' Bill and Resolutions.

PETTION RE PRICE, PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF MOLASSES

SHRI M. N. REDDY : (Nizamabad) I beg to present a petition from Shri B. Saya Reday of Mosra, Taluk Bodhan, District Nizamabad (Andhra Pradesh), regarding control, on price, production and distribution of molasses.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned till twenty minutes past Fourteen of the Clock.

———

The Lok Sabha re-assembled after lunch at twenty two minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI M. B. BANA *in the Chair*]

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS BILL—*Contd.*

Clause 2 (*Definitions*)

MR. CHAIRMAN : We take up clause by clause consideration.

First we shall take up clause 2. There are some amendments. They may be moved.

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : I beg to move :

Page 1,-

Omit lines 10 and 11. (4)

SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : (Meerut) : I beg to move :

Page 2, —

for lines 2 to 5, *substitute*—

"column 1 of the First Schedule". (5)

SHRI GEORGE FERNANDES (Bombay South) : I beg to move :

Page 1, line 10, —

for "does not include" *substitute* "includes" (13)

Page 1, line 11,—

add at the end—

"but does not include Co-operative Banks registered under the Co-operative Societies Act". (14)

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon): I beg to move :

for "fifty" *substitute* "hundred". (44)

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) : I beg to move :

Page 1, Line 10,—

omit "not" (46)

Page 2.—

for lines 1 to 5, *substitute*—

(b) "existing bank" means any banking company that is in existence in India within the meaning of the Companies Act, 1956. (47)

SHRI ABDUL GHANI DAR : I beg to move ;

Page 2, line 1,—

after "banking company", *insert*—

"including foreign banking company". (62)

Page 2,—

for lines 1 to 5, *substitute*

(b) "exisiting bank" means a banking company'. (63)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :

Page 1, line 10,

for "banking company" does not include a foreign Company *substitute*

' "banking company" includes both indigenous and foreign company'.(106)

Page 2,—

for lines 1 to 5, *substitute*

'(b) "existing bank" means a banking company both indigenous and foreign specified in column 1 of the First Schedule with the persent deposits as shown in the return as on the last Friday of June, 1969.' (107)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P.C. SETHI) : I beg to move :

Page 2, line 13—

for "the" *substitute* "a" (119)

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) beg to move :

Page 1,—

for lines 10 and 11, *substitute*—

'(a) "banking company" means a banking company as defined in section 5(c) of the Banking Regulation Act, 1949 but excludes co-operative banks.'(154)

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : I beg to move :

Page 2,—

for lines 1 to 5, *substitute*

(b) "exisiting bank" means a banking comp ny incorporated in India or outside excluding Industrial Development Bank of India, the Reserve Bank, the State Bank of India and its subsidiaries functioning in the country, cooperative Banks or Banks carried managed by public bodies like municipality are excluded from this definition'. (82)

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Viskhapatnam) : I beg to move :

Page 2, lines 5,—

for "fifty" *substitute* "twenty-five" (169)

SHRI MADHU LIMAYAE : I beg to move :

Page 2,—

after line 16, *insert*—

'(h) "rural area" means village and small towns with a population of not more than ten thousand". (175)

SHRI KUNDU (Balsore) : I beg to move :

Page 2, line 2,—

after "Schedule" *insert*—

"and any such other banks," (204)

Page 2, line 5,—

for "fifty crores" *substitute*—

"one crore except such other banks run on the cooperative sector" (205)

SHRI N. DANEKER (Jamnagar) : I beg to move :—

Page 2, line 5,—

for "fifty crores", *sudstitute* "two hundred crores". (281)

SHRI NABIAR (Tirchirappali) I beg to move :

Page 1, line 10,—

omit "does not" (317)

Page 2, line 5,—

for "fifty" *substitute* "twenty" (318)

SHRI BIBHUTI MISRA (Motihari) : I beg to move :

Page 2, line 2,—

omit "column 1 of the First Schedule" (335).

Page 2, line 5,—

omit "where not less than rupees fifty crores" (336)

Page 2,—

(i) line 6, *for* "existing bank" *substitute* "existing banks"

(ii) *omit* lines 7 and 8 (337)

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR (Kishanganj) : I beg to move :

Page 2, line 2,—

after "Schedule" *insert*—

"and such other banks having deposits not less than a crore of rupees except the cooperative banks and shall include all foreign banks in India."(370)

Page 2, line 5,—

for fifty" *substiiute* "one" (371)

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : I beg to move :

Page 1, line 10,

omit "not" (380)

Page 2, line 1,

after "specified" *insert*—

"and to be specified in future" (381)

Page 2, line 5,—

for "crores" *substitute* "lakhs"(382)

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : (Ratnagiri) : I beg to move:

Page 1,

for lines 10 and 11, *substitute*-

(a) "banking company" includes a foreign company within the meaning of section 591 of the Companies Act 1956.' (197)

Page 2,

for lines 1 to 5, *substitute*-

(b) "existing banks" means all banks." (198).

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, समय बचाने के लिए इस क्लाज पर अपने दोनों संशोधनों को मैं एक साथ पेश कर रहा हूं ।

मेरा पहला संशोधन यह है । पृष्ठ 1 पर बैंकिंग कम्पनी की परिभाषा की गई है । इस विधेयक में बताया गया है कि कम्पनी कानून के खण्ड 591 में बैंकिंग कम्पनी की जो परिभाषा बताई गई है उसका शुमार इसमें नहीं होगा । इसका साफ़ मतलब है कि आगे हम लोग जो संशोधन करने वाले हैं—पहले शेड्यूल में और दूसरी धाराओं में—वह नहीं हो पाएगा, यदि हमारा संशोधन मंजूर नहीं होगा । इसलिए मैंने यह एक बहुत बुनियादी संशोधन रखा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीयकरण का विधेयक आया है. इसमें केवल भारत के बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण किया जाय, ऐसा नहीं होना चाहिये, इसमें कुछ विदेशी बैंकों का भी तत्काल समावेश होना चाहिये । 50 करोड़ वाली इनकी जो सीमा है, उसको मद्दे-नज़र रखते हुए जो नये आंकड़े मुझे मिले हैं, उनसे इन बैंकों के बारे में स्थिति बिलकुल साफ़ है ।

नेशनल ग्रिण्डले बैंक, जिसमें लायड्स बैंक भी मिल गया है, दूसरा—चार्टर्ड बैंक और तीसरा फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक, जो कि एक अमरीकी बैंक है—इनके डिपाज़िट्स 50 करोड़ रुपये से अधिक हैं । मर्केंटाइल बैंक के बारे में थोड़ा सन्देह हो सकता है, लेकिन यदि उसके बारे में भी ताज़े आंकड़े मिल जांय, तो शायद पता चलेगा कि इस बैंक का डिपाज़िट भी 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। क्योंकि 2 साल पहले का जो आंकड़ा मेरे पास है, उसके अनुसार उस वक्त इसका डिपाजिट 42-43 करोड़ रुपये के करीब था । इसलिए इसके बारे में मंत्री महोदय खुलासा कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि इस सरकार और सत्ताधारी दल की नीति है कि विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। जब सरकार विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो क्या वजह है कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये ये लोग तैयार नहीं हैं।

कल अपने भाषण में प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ये जो विदेशी बैंक हैं उनका फायदा हम लोगों को विदेशी व्यापार के क्षेत्र में होता है, लेकिन जब विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की चर्चा चल रही है, तो विदेशी बैंकों को नहीं छोड़ना चाहिये, कम से कम 50 करोड़ वाले बैंकों को तो बिलकुल नहीं छोड़ना चाहिये । इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमारे संशोधन को स्वीकार करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी व्यापार का मामला इसमें जुड़ा हुआ है—स्वयं प्रधान मंत्री ने इस को कहा है। हमारा व्यापार पूर्वी यूरोप के साथ बढ़ रहा है । पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट प्रणाली है । वहां सभी उद्योग धन्धे राष्ट्र की मिल्कियत हैं—वहां पर व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण हो गया है । उन देशों के साथ हमारा व्यापार, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के रहते हुए भी, निजी क्षेत्र में क्यों हो रहा है ? इसलिए सबसे पहले तो विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और कम्युनिस्ट देशों के साथ एस० टी० सी० या जो ऐसे दूसरे सरकारी साधन हैं उनके जरिए व्यापार होना चाहिए ।

दो तीन रोज पहले वित्त मंत्री की ओर से मेरे यहां एक पत्र आया है । नैपाल से हमारे पास जो सिंथेटिक फैब्रिक्स और स्टैनलैस स्टील वगैरह आता है, उसके बारे में नवम्बर के महीने में, मैंने सुझाव दिया था कि जो करार हुआ है उसका पालन करने के लिये नैपाल से हमारे यहां जितना माल आयेगा वह एस० टी० सी० की मार्फत आये । मंत्री महोदय लिखते हैं कि नैपाल को कबूल नहीं है। लेकिन अगर तस्कर व्यापार को रोकना है तो एस०टी०सी० की मार्फत ही आयात होना चाहिये । इसके लिए जरूरी है कि विदेशी बैंकों पर भी हमारा कब्जा हो । जब तक उन पर हमारा कब्जा नहीं होगा,

तब तक आप यह काम कर नहीं पायेंगे । इसलिए मैं मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि विदेशी बैंकों के बारे में ये जो व्याख्यायें दी गई हैं, इसमें मेरा जो संशोधन है बैंकिंग कम्पनी के बारे में उनको कबूल करें ।

मैं अपना दूसरा संशोधन भी रखना चाहता हूं जिसमें ग्रामीण इलाके की परिभाषा करने का प्रयास किया गया है । स्टेट बैंक की नई रिपोर्ट आप खोलेंगे तो देखेंगे कि ग्रामीण इलाके में वह बहुत शाखायें खोल रही है । लेकिन इनकी जो परिभाषा है उसमें 25 हजार वाले शहर भी ग्रामीण इलाके में शामिल हैं । तो 25 हजार वाले शहर ग्राम नहीं कहे जा सकते ।...(व्यवधान)...इसीलिए मैंने बीच का रास्ता दिया है । 25 हजार वाला शहर ग्राम हो नहीं सकता है । इसलिए ग्रामीण इलाके की परिभाषा बदल कर, जैसा कि मैंने कहा है, आप दस हजार या दस हजार से कम वाले जो देहात हैं सिर्फ उनका ही समावेश ग्रामीण इलाके में कीजिए । यदि आप काश्तकारों को भी ऋण देना चाहते हैं और खेती की उन्नति करना चाहते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी बैंकों की आदत और व्यवस्था का प्रसार करना चाहते हैं तो आपको मेरी इस तरमीम को स्वीकार करना चाहिए । ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी ये दोनों बुनियादी तरमीमें हैं, इनको कबूल कीजिए ।

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : सभापति महोदय, जो बैंक लिये जा रहे हैं इनके पीछे जो एक बड़ा आदर्श है वह यह है कि जो बड़े लोग हैं वह तो बक से लेते हैं, बैंकों में देते नहीं हैं, और जो माध्यम वर्ग के लोग हैं वह साधारणतया बैंकों से लेते नहीं हैं, बैंकों को देते हैं । आम आदमी का रुपया इकट्ठा होते-होते चार हजार करोड़ तक पहुंच जाता है । जब यह तय किया गया कि नेशन के हित में, देश के विकास के लिए इस रुपये का इस्तेमाल हो, न कि चन्द आदमियों के विकास के लिए हो तो फिर इन में से कुछ बैंकों को छोड़ देना और कुछ को ले लेना, यह बात उचित नहीं हो सकती है । जो बैंक आप छोड़ रहे हैं, उनकी जो लिस्ट आपने दी है उसी में मेरा संशोधन है कि जो शिड्यूल्ड बैंक हैं वही लिए जायं । बाकी जो आपने बात रखी है कि 50 करोड़ से नीचे वाले न लिये जायें उसमें आज जो 50 करोड़ से नीचे हैं वह कल 51 करोड़ के हो जायेंगे और फिर उनको लेने की बात उठेगी । इस तरह से आप एक मौका दे रहे हैं कि जो लोग गड़बड़ करना चाहते हैं वे इसके जरिए गड़बड़ करते रहें । 21 साल में इस सरकार ने जो एक मजबूत कदम उठाया है इसके लिए मेरा जैसा आदमी यही कहेगा कि जिनके औलाद होतीं नहीं थी उनके 21 साल में पहली बार औलाद हुई, बहुत बढ़िया लौंडा हुआ—पूरे मुल्क ने खुशी मनाई । लेकिन जब शानदार औलाद हो गई है तो फिर आप इसके हाथ पैर क्यों बांधना चाहते हैं । आप तबियत के साथ अपना काम करो चाहे उससे सिंडीकेट को झटका लगे या पूंजीवादियों को झटका लगे । अब इसमें आपकी हिचकिचाहट अच्छी नहीं लगती है । आपने पहली बार एक फाइनेंस जनता के लिए खोला है—जनता आपका इस्तकबाल कर रही है । जनता ने महसूस किया है कि पहली बार यह फंड हमारे काम आने वाला है । इसलिए मेरा संशोधन है कि उसमें से विदेशी वाला मामला या 50 करोड़ से नीचे वाला मामला, यह सब हटा दीजिये और सिर्फ यह रखिये कि जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनको लिया जायेगा ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मेरा जो संशोधन है उस पर मैं दो मोटी बातें रखना चाहता हूं । एक तो बैंकिंग कम्पनी की जो डेफनीशन है जिसमें विदेशी बैंकों को हटाने की बात हुई है उसमें सिर्फ कोआपरेटिव बैंक्स को इस विधेयक से अलग रखना चाहता हूं । मेरा जो दूसरा संशोधन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मुझे बड़ी खुशी है कि इस संशोधन को

[श्री जार्ज फरनेंडीज]

कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों की ओर से भी लिखित समर्थन मिला है—जैसे श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती सुचेता कृपलानी, रमेश चन्द्र व्यास, श्री महाजन, श्री गंगा रेड्डी—इन तमाम लोगों का लिखित समर्थन मिला है और शायद प्रधान मंत्री को इन लोगों ने एक चिट्ठी भी लिखी है कि देश के और विदेश के तमाम बैंक जो इस समय हिन्दुस्तान में हैं उन सभी का राष्ट्रीयकरण हो। मैंने सभी लोगों के नाम नहीं पढ़े हैं क्योंकि वह सूची बहुत लम्बी है। इन्होंने प्रधान मंत्री से इजाजत मांगी है कि उन को मेरे संशोधन के समर्थक में वोट देने का मौका दिया जाय। पिछले कई दिनों से जो तर्क यह मैं सुन रहा हूं, कभी प्रधान मंत्री के मुंह से, कभी कानून मंत्री के मुंह से, कभी अन्य कांग्रेसियों के मुंह से और कभी और लोगों के भी मुंह से कि देश के ये 14 बैंक छोड़कर और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं थी और विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे बहुत ही भारी और परेशानी का काम होगा। लेकिन इन तर्कों में मुझे कोई तर्क दिखाई नहीं देता है। मैं प्रधान मंत्री को अपने ही एक पड़ोसी देश जोकि हमसे बहुत छोटा लेकिन कुछ मामलों में हमसे बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, उसका उदाहरण देना चाहता हूँ—वह है बर्मा। उसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उसमें देशी और विदेशी के झंझट में नहीं पड़ा। बर्मा में हिन्दुस्तान की बैंकों की भी तो शाखायें थी उनका भी राष्ट्रीयकरण किया। अब आप कह सकते हैं कि बर्मा हिन्दुस्तान से लड़ने या हिन्दुस्तान के मुकाबले में खड़ा होने की हिम्मत रख सकता है लेकिन हम अंग्रेजों के मुकाबले में...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : I presume you are speaking on all the three amendments.

श्री जार्ज फ़रनेंडीज : उसके साथ में 27 नम्बर का जो शेड्यूल है उसको ही पूरा अमेण्ड करना चाहता हूं। मैं तो पूरे शेड्यूल को ही बदलना चाहता हूं। जो बी है :

> "Existing bank" means a banking company specified in column 1 of the First Schedule."

वहीं तक सीमित रखना चाहता हूं और 50 करोड़ वाली बात को हटाना चाहता हूं। तो बर्मा को जो हिम्मत रही, अगर प्रधान मंत्री कहती हैं कि बर्मा हमसे बड़ा तगड़ा देश है, बड़ा हिम्मत वाला है और यदि हम कमजोर हैं अंग्रेजों के मुकाबले में, जापान के मुकाबले में, अमरीका के बैंकों के मुकाबले में, क्योंकि तीन मुल्कों के बड़े बैंक यहां हैं, इनके मुकाबले में बर्मा ने जो हिम्मत की वह हमारा भारत नहीं कर सकता है तो फिर यह तर्क बेकार का होगा। और कांग्रेस पार्टी के भी कई लोग जैसे माननीय तारकेश्वरी जी और श्रीमती सुचेता कृपलानी जी इस पर कोई विश्वास नहीं रख रही हैं।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जो तर्क आप देते हो राष्ट्रीयकरण के समय कि यह पैसा पूंजीवादियों के हाथों में रहता है, जैसे ओरियन्टल बैंक आफ़ कामर्स है, मोनोपलीज कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार करम चन्द थापर की जो कम्पनियां हैं, जो इस समय भारत में चौथी या पांचवीं सबसे बड़ी मोनोपली है, लगभग 100 करोड़ रु० उनकी सालाना आमदनी है, लेकिन इस मोनोपली का जो बैंक है ओरियन्टल बैंक आफ़ कामर्स, ताजे आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं, उसके पास 20, 30 करोड़ रु० हो चुके हैं। रिजर्व बैंक की जो स्टेटिस्टिकल टेबिल मिली है 1967 की; उसके बाद की नहीं आयी, इस समय कितना पैसा इस बैंक के पास है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन 1967 के अन्त में उनके पास 12 करोड़ रु० थे और इस समय तक 25, 30 करोड़ रु० जरूर होंगे। तो यह जो इतना बड़ा बैंक है, आप अगर यह तर्क दो कि नहीं चूंकि उस बैंक के पास 25, 30 करोड़ रु० हैं और हमारा जो साउन्ड बैरियर 50 करोड़ का उसमें चूंकि

वह नहीं आता इसलिये हम उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, इसमें कोई तथ्य नहीं है ।

आज ही सुबह मेरे पास आंध्रा बैंक के कर्मचारियों की ओर से एक तार, पत्र आया है, इस बैंक की लगभग सवा सौ शाखायें हैं, आठ हजार कर्मचारी इसमें काम करते हैं, और इस समय उस बैंक के पास 40 करोड़ से भी अधिक रकम है । लेकिन उसको आप नहीं ले रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता । इसलिये मेरा संशोधन है कि जो आप इस समय राष्ट्रीयकरण की बातें करते हो तो यह अधूरा वाला राष्ट्रीयकरण न चलाओ बल्कि देश में सभी बैंकों को इसमें लीजिये । शेड्यूल्ड और नान-शेड्यूल्ड वाला अन्तर भी हम लोग न करें । रिजर्व बैंक की 1967 की स्टेटिस्टिक्स के अनुसार कुछ ऐसे बैंक हैं जो नान-शेड्यूल्ड हैं, जैसे कैथोलिक सीरियर बैंक, त्रिचूर । इस बैंक के पास पांच करोड़ से भी अधिक रुपये थे 1967 के बाद । इस समय पता नहीं उसके पास सात, आठ, दस करोड़ रु० हों ।

दूसरे बैंक हैं, जैसे बैंक आफ़ करा, बैंक आफ़ कोचीन, फेडरल बैंक आफ़ आलवे, करोड़ों रु० इन बैंकों के पास पड़ा है । क्यों अभी तक इन को नान-शेड्यूल्ड रखा यह वह जानें । लेकिन हमें यह फ़र्क नहीं करना चाहिये पैसे का । जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसका पूरे का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

अगर सरकार का वह दिमाग बना हो कि पूंजी और पूंजी का इस्तेमाल करने वाली संस्थायें लोगों के हाथों में नहीं रहनी चाहिये तो उनको अपने हाथों में लेकर, विदेशी और देशी का फ़र्क खत्म कर के सबको नेशनेलाइज किया जाये । मेरी प्रार्थना है माननीय तारकेश्वरी जी से तथा सभी सदस्यों से जिन्होंने प्रधान मंत्री को भेजे गये पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, उन सब से प्रार्थना है कि उनके नेता इजाजत दें या न दें, वे हमारे साथ इस पर वोट करें और यह बतायें कि जिन चीजों को लेकर यहां आज बहस हो रही है उसको हम गम्भीरता के साथ लेते हैं । जब कि कुछ लोगों का आरोप है कि प्रधान मंत्री जी और सरकार इस पर अत्यन्त गम्भीरता के साथ नहीं सोच रही है, बल्कि एक राजनीतिक ढंग से सोच रही है ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : चेयरमैन साहब, मैं इंदिरा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है । उन्होंने जो कहा था उसकी ही रोशनी में मैंने अपनी अमेंडमेंट इस बिल पर मूव की है । एक तो उन्होंने यह कहा था कि चूंकि कुछ बैंकों ने सोशलाइजेशन के बारे में, सोशल कंट्रोल के बारे में कोआपरेशन नहीं दिया इसलिए जरूरी था कि इसको किया जाये । नाम तो इन्होंने नहीं लिये कि कौन से बैंक थे जिन्होंने प्रधान मंत्री और मोरार जी भाई को कोआपरेशन नहीं दिया । मैं कहना चाहता हूँ कि इनके दिमाग में जो बंगलौर में 5, 6 बैंक थे, मैं यह समझा था कि वही बैंक होंगे जिन्होंने कोआपरेशन नहीं दिया और उन्हीं का यह नेशनेलाइज करना चाहती हैं, और एक तजुर्बा भी करना चाहती हैं कि उससे कितना किसान को, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेबरर को और पेजेन्ट को कितना फायदा पहुंचता है ।

मैंने यह कहा है कि अगर आप इसमें अब अन्तर करती हैं, आप को यह अख्तियार है, आप ने 14 बैंकों का नाम लिया, आप कितने ही बैंकों के नाम लें, मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि उन बैंकों में ऐसे बैंक भी हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री को या साबिक फाइनेंस मिनिस्टर श्री मोरार जी देसाई को कोआपरेशन दिया । लेकिन फिर भी एक मसला था कौम के सामने । मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कामयाब हों, उस तरह से हमें फेल्योर मुंह न देखना पड़े, जैसा एल० आई० सी० में हुआ । कल से जिक्र होता रहा, हमें मौका नहीं मिला, इसका कोई रंज नहीं । आप को मालूम होगा कि एल० आई० सी० के

[श्री अब्दुल गनी डार]

रुपये में से किसानों को कुछ नहीं मिला, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई कर्जा नहीं मिला पेजेन्ट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि एक्सपेंडिचर की रेशियो बढ़ी, लैप्स रेशियो बढ़ गई और उसमें नुकसान हुआ।

दूसरा सवाल यह किया जाता है कि पब्लिक सैक्टर में 2500 करोड़ रु० का नुकसान होता है, या 25 करोड़ का नुकसान होता है, जैसा कि मेरे एक भाई कह रहे हैं, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री जी ने हिम्मत की है, तो मैं माननीय मधु लिमये जी और माननीय फ़रनेन्डीज से सहमत हूं, इत्तफ़ाक करता हूं कि फिर इन फोरेन बैंक्स को क्यों छोड़ें? उन्होंने कहा कि इसलिये छोड़ देते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें उनसे मदद मिलती है। मदद मिलती होगी। अव्वल तो सच्ची बात यह है, अगर वह बुरा न मानें, कि एशिया और हमारी सरकार एक ही बोली बोल रही है, कम्युनिस्टों और इंदिरा जी में फर्क नहीं है। फोरेन बैंक्स हमारी क्या मदद करेंगे। जब हमको एशिया से ही सारा काम करना है, इनकी ही तूती बोलनी है तो फोरेन बैंक्स को, मैंने यह कहा है, कि अलग नहीं करना चाहिये। और यह प्रोवीजो उड़ा दिया जाये तथा बैंकिंग की जो तारीफ है उसमें फोरेन बैंक्स हों, या अपने बैंक हों उनको लाया जाये।

दूसरी बात जो मैंने यह कही है कि 50 करोड़ के बजाए 100 करोड़ हो तो कम्युनिस्टों ने एतराज़ किया कि यह तो री-एक्शनरी हो गया। मैंने यह इसलिए कहा था कि इनके दिमाग में पांच-छः बैंक थे जिन्होंने इनको कोआपरेशन नहीं दिया था। इस पर कम्युनिस्ट भाइयों को बड़ा ऐतराज़ है। ये लोग पब्लिक सैक्टर के वैसे तो बड़े पुरजोश हामी हैं और इनका शायद यह ख्याल रहा कि इंदिरा जी की तब हिमायत होती है जब पब्लिक सैक्टर कामयाब हो। यह हिमायत नहीं है कि सैबोटाज करो, घेराव करो, इंडस्ट्री को बरबाद करो, और फिर भी कहें कि हम नेशनल हैं और मैं रीऐक्शनरी हूं जो इसके खिलाफ़ कहता हूं।

मैंने कहा है कि बजाय 50 करोड़ के 100 करोड़ किया जाय। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ा मुश्किल और कठिन काम है जो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है। जिम्मे मैं इसलिए कहता हूं कि काफी लोग हैं जो उन का साथ बजाहिर देंगे लेकिन दर हकीकत उन को हर कदम-कदम पर सैबोटाज करेंगे। मैं गालिबन कल ही यहां दो खत तकसीम करने वाला हूं। बात यह है कि मैंने श्रमती इदिरा गांधी को प्यार दिया कि उन्होंने दिलेरी से कदम उठाया, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह याद रक्खें, और मैं बरसों से यह कहता रहा हूं, कि इन बैंकों के डाइरेक्टरों और रिजर्व बैंक के अफसरों ने मिलकर गरीबों के करोड़ों रुपये बरबाद किये। इसके लिए मैंने अपनी कोशिशें जारी रक्खीं और किताबों पर किताबें शाया कीं पूरी जिम्मेदारी के साथ। इसके लिए मुझ पर केस भी चल रहा है मद्रास में। लेकिन मैं चिन्ता नहीं करता चाहे मेरे खिलाफ दस मुकदमे चला करें। मैंने अपनी बात कही। आज उन मगर मच्छों के खिलाफ कोई मुकदमा चलने वाला नहीं है जिनकी मैंने मांग की, या जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वालों ने, एस० एस० पी० वालों ने या जनसंघ वालों ने या इंडेपेन्डेंट्स ने मांग की। मैं प्रधान मंत्री से दर्ख्वास्त करता हूं कि उन खराब डाइरैक्टरों के खिलाफ़ जिन्होंने बैंकिंग को बदनाम किया, जिन्होंने कोआपरेशन नहीं दिया, ऐसे बददयानत डायरेक्टरों के खिलाफ और ऐसे रिजर्व बैंक के बददयानत अफसरों के खिलाफ़ वह फौरन जुडिशल एन्क्वायरी बिठलायें। मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह से एस.आर. दास ने हमारे हक में अन्याय किया था और हमारे साबिक प्रधान मंत्री और साबित चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हार गये उसी तरह से यह डाइरैक्टर हारने वाले हैं।

प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह उनका गला पहले घोटें बजाए इसके कि वह रास्ते में आयें और उनको तंग करें। जितने भी मगर मच्छ हैं शांति प्रसाद जैन जैसे, जिनका नाम कल श्री मधु लिमये ने नहीं लिया, शुक्र है कि श्री जार्ज फरनेंडीज ने करम चन्द थापर के नाम का जिक्र कर दिया, और इस तरह के जो दूसरे मगर मच्छ हैं, सबको साथ लिया जाये।

मेरी दर्ख्वास्त है कि फारेन बैंकों को भी इसमें साथ लाया जाय और जो भी खराब डाइरेक्टर हैं उनके खिलाफ़ जुडिशल प्रोब करके उनको कटघरे में लाया जाये ताकि प्रधान मंत्री को अपने काम में मदद मिले। उनके काम में सुभीता हो। यह मेरी दिली ख्वाहिश है।

मैं एक पर्सनल एक्स्प्लेनेशन भी देना चाहता हूं। कुछ दोस्तों के ख्याल हैं कि मैं उन की पार्टी पालिटिक्स में पड़ने वाला हूं। शायद मैं मोरार जी देसाई की तरफ हो जाऊं या इंदिरा गांधी की तरफ हो जाऊं। बिल्कुल यह बात नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं बिल्कुल इस बिल के साथ हूं। मैंने सिर्फ यह कहा था कि इस वक्त कोई इमर्जेन्सी नहीं है, इसलिए जिस तरह से यह आर्डिनेंस लाया गया उससे मुझे दुःख हुआ। जिस तरह से यह आर्डिनेंस लाया गया वह गलत था। इसलिए यहां पर कोई यह दलील न दे कि यह उनके साथ हैं वह उनके साथ हैं। जो मैं बोल रहा हूं उस के यह माने नहीं हैं कि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ नहीं हूं। लेकिन मेरा कहना यही था कि इस वक्त कोई इमर्जेन्सी नहीं थी और जो कुछ हुआ है वह डिप्लोरेबल था, गलत था।

[شری عبدالغنی ڈار - (گوڑگانوہ) چیرمین صاحب میں اندراجی کو بدھائی دیتا ہوں کہ انھوں نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے انھوں نے جو کہا تھا کہ اس کنٹرول میں میں نے اپنی امینڈمینٹ اس بل پر موو کی ہے۔ ایک تو انھوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ کچھ بینکوں نے سوشلائزیشن کے بارے میں سوشل کنٹرول کے بارے میں کوآپریشن نہیں دیا اس لئے ضروری تھا کہ اس کو کیا جائے۔ نام تو انھوں نے نہیں لیا کہ کونسے بینک تھے جنہوں نے پردھان منتری اور مرارجی بھائی کو کوآپریشن نہیں دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہی بینک ہونگے جنہوں نے کوآپریشن نہیں کیا اور انھیں کو یہ نیشنلائز کرنا چاہتی ہیں اور ایک تجربہ بھی کرنا چاہتی ہیں کہ اس سے کتنا کسان کو، چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو لیبر اور پیزنٹس کو فائدہ پہنچتا ہے۔

میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں انٹر کرتی ہیں۔ جو آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے چودہ بینکوں کا نام لیا۔ کتنے ہی بینکوں کے نام لیں مجھے کوئی گریز نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ ان بینکوں میں ایسے بینکس بھی ہیں جنہوں نے پردھان منتری کو یا سابق فائننس منسٹر، شری مرارجی ڈیسائی، کو کوآپریشن دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بڑا مسئلہ قوم کے سامنے تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں۔ پردھان منتری کامیاب ہوں اور اس طرح سے ہمیں فیلیور کا منہ نہ دیکھنا پڑے جیسا کہ ایل۔ آئی۔ سی میں ہوا۔ کل سے ذکر ہوتا رہا مجھے موقع نہیں ملا۔ اس کا کوئی رنج نہیں لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ایل۔ آئی۔ سی کے روپے میں سے کسانوں کو چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو پیزنٹس کو کوئی قرضہ نہیں ملا۔ جبکہ ایکسپینڈیچر کی ریشیو بڑھی۔ یہیں ریشیو بڑھ گئی اور اس میں نقصان ہوا دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بینک سیکٹر میں ۲۵ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے یا ۲۵ کروڑ کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ میرے ایک بھائی کہہ رہے ہیں۔ میں اس میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر پردھان منتری جی نے ہمت کی ہے تو میں مانیہ مدھولمائی جی اور مانئے فرنینڈیز جی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان فارن بینکس کو کیوں چھوڑیں۔ انھوں نے

کہا کہ اس نئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے اس میں ان سے مدد ملتی ہے ان سے مدد ملتی ہوگی۔ اول تو یہی بات یہ ہے اگر وہ برا نہ مانیں کہ رشیا اور ہماری سرکار ایک ہی بولی بول رہی ہے۔ کمیونسٹوں اور اندرا جی میں کوئی فرق نہیں ہے فارن بینکس ہماری کیا مدد کریں گے۔ جب ہم کو رشیا سے ہی سارا کام کرنا ہے ان کی طوطی بولتی ہے تو فارن بینکس کو میں نے یہ کہا ہے کہ الگ نہیں کرنا چاہئے اور یہ پرودیزو اڑا دیا جائے۔ اور بینکوں کی جو تعریف اس میں فارن بینکس ہوں یا اپنے بینکس ہوں ان سب کو لایا جائے۔

دوسری بات جو میں نے یہ کہی ہے کہ ۵۰ کروڑ کے بجائے ۱۰۰ کروڑ ہو تو کمیونسٹوں نے اعتراض کیا کہ یہ فوری ایکسٹری ہو گیا۔ میں نے یہ اس لئے کہا تھا کہ ان کے دماغ میں پانچ چھ بینک تھے۔ جنہوں نے ان کو کوآپریشن نہیں دیا تھا اس پر کمیونسٹ بھائیوں کو بڑا اعتراض ہے یہ لوگ پبلک سیکٹر کے ویسے تو بڑے پرجوش حامی ہیں اور ان کا شاید یہ خیال رہا ہے کہ اندرا جی کی تب حمایت ہوتی ہے جب پبلک سیکٹر کامیاب ہو۔ یہ حمایت نہیں ہے کہ سبوتاژ کرو گھیراؤ کرو، انڈسٹری کو برباد کرو اور پھر بھی کہیں کہ ہم نیشنل ہیں اور میں رئی ایکسٹری ہوں جو اس کے خلاف کہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ بجائے پچاس کروڑ کے ۱۰۰ کروڑ کیا جائے۔ میں پردھان منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے جو انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ذمہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ کافی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بظاہر ہونگے۔ لیکن میں درحقیقت ہر قدم پر ان کو سبوتاژ کریں گے۔ غالباً کل ہی یہاں دو خط تقسیم کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے شریمتی اندرا گاندھی کو بدھائی دیا کہ انھوں نے دلیری سے قدم اٹھایا۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں۔ اور میں برسوں سے یہ کہتا آرہا ہوں کہ ان بینکوں کے ڈائریکٹروں اور رزرو بینک کے افسروں نے مل کر غریبوں کے کروڑوں روپئے برباد کئے۔ اس کے لئے میں میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور کتابوں پر کتابیں شائع کیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے لئے مجھ پر کیس بھی چل رہا ہے۔ مدراس میں۔ لیکن میں چنتا نہیں کرتا چاہے میرے خلاف دس مقدمے چلا کریں۔ میں نے اپنی بات کہی۔ آج ان مگرمچھوں کے خلاف کوئی مقدمہ چلنے والا نہیں ہے جن کی میں نے مانگ کی۔ یا جن کی کمیونسٹ پارٹی والوں نے۔ پرجا سوشلسٹ والوں نے۔ ایس۔ ایس۔ پی والوں نے یا جن سنگھ والوں نے یا انڈیپینڈینٹس نے مانگ کی۔ میں پردھان منتری سے درخواست کرتا ہوں کہ ان خراب ڈائریکٹروں کے خلاف جنہوں نے بینک کو بدنام کیا۔ جنہوں نے کوآپریشن نہیں دیا ایسے بددیانت ڈائریکٹروں کے خلاف اور ایسے رزرو بینک کے بددیانت افسروں کے خلاف فوراً جوڈیشل انکوائری بٹھلائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح سے ایس۔ آر۔ داس نے ہمارے حق میں نیائے کیا تھا اور ہمارے سابق پردھان منتری اور سابق چیف منسٹر پنجاب ہار گئے اس طرح سے یہ ڈائریکٹر ہارنے والے ہیں۔ پردھان منتری کو چاہیے کہ وہ ان کا گلا گھونٹیں۔ بجائے اس کے کہ وہ راستے میں آئیں۔ اور وہ ان کو تنگ کریں۔ جتنے بھی مگرمچھ ہیں شانتی پرشاد جین جیسے جن کا نام کل شری مدھو لیمیے نے نہیں لیا۔ شکر ہے کہ شری جارج فرنینڈیز نے کرم چند تھاپر کے نام کا ذکر کر دیا اور اس طرح کے جو دوسرے مگرمچھ ہیں سب کو ساتھ لیا جائے۔

میری درخواست ہے کہ فارن بینکوں کو بھی اس میں ساتھ لایا جائے اور جو بھی خراب ڈائریکٹر

ہیں ان کے خلاف جوڈیشل پروب کر کے ان کو
کٹگھرے میں لایا جائے تاکہ پردھان منتری کو اپنے
کام میں مدد ملے۔ ان کے کام میں سمجھتا ہوں یہ
میری دلی خواہش ہے ۔

میں ایک پرسنل ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں۔
کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ میں ان کی پو پالیٹکس پارٹی
میں پڑنے والا ہوں۔ شاید میں مرار جی ڈیسائی
کی طرف ہو جاؤں اور اندرا گاندھی کی طرف
ہو جاؤں۔ بالکل یہ بات نہیں ہے۔ جہاں تک
میرا سمبندھ ہے۔ میں بالکل اس بل کے ساتھ ہوں۔
میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس وقت کوئی امرجنسی نہیں
ہے اس لئے جس طرح سے آرڈیننس لایا گیا اس سے
مجھے دکھ ہوا۔ جس طرح سے یہ آرڈیننس لایا گیا وہ
غلط تھا۔ اس لئے یہاں پر کوئی یہ دلیل نہ دے
کہ یہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جو
میں بول رہا ہوں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ میں
شریمتی اندرا گاندھی کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن میرا
کہنا یہی تھا کہ اس وقت کوئی ایمرجنسی نہیں تھی اور
جو کچھ ہوا ہے وہ ڈیپلوریبل تھا۔ غلط تھا۔]

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh) : Mr. Chairman, Sir, I wanted to take part in the general discussion of this Bill but, unfortunately, the number of speakers from the Congress Party was so large that we could not be accommodated.

I take this opportunity of speaking on this amendment because I feel that banks which have not been nationalised will create a kind of discrimination not only between depositors but also between creditors. We had 79 scheduled banks out of which 14 banks have been nationalised now and earlier the Imperial Bank and banks in some Indian States—seven of them...were nationalised ; all together there are 22 banks which are nationalised banks. Yet. out of these 49 banks, when I see the composition of scheduled banks I find that three foreign banks...the National and Grindlays Bank, the Chartered Bank and the First National City Bank of America will now carry three-fourths of the desposits of all the 49 scheduled banks. They will distribute nearly two-thirds of the credit of those banks which have been kept outside the purview of nationalisation. I have never been able to understand this.

The very contention of the Prime Minister's note to the Bangalore AICC was to give an orientation to our economy. This has been the reason why in the 10-point programme it is specifically mentioned that while LIC was nationalised, the general insurance was not nationalised and, therefore, the general insurance needs to be brought under the purview of nationalisation. If that connotation could be applicable there, that connotation is very much applicable here.

I have never been able to understand how we can discriminate between a depositor and a depositor. Apart from the legal tenability which looks to me a very doubtful feature today, we cannot discriminate between a depositor and a depositor. I cannot understand that. A depositor will invest his money in the nationalised banks ; he will invest his money in the non-nationalised banks and he will also be free to invest his money in the foreign banks. Nobody can stop him from doing that. No Government can ever legislate or issue a direction, asking a depositor to do this and not to do that. That will be a violation of the fundamental right of a depositor. It will be illegal. I think, the Government should consider this matter in a cooler manner, not in a political huff and with slogan-mongering. These are the things that have to be considered on merit. I think, no discrimination can be made between a depositor and a depositor and even between a creditor and a creditor, When a creditor want to take money from a nationalised bank, he will be guided by certain directions and guide-lines which will be prescribed by the Government or by the Reserve Bank or whosoever it may be. But when a creditor goes to a non-nationalised bank or to a foreign bank, he will be in a much better position to go and invest the money in any industry he likes. I do not know whether the directions issued by the Government will be tenable.

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

Now, there is the National and Grindlays Bank with deposits of more than Rs 168 crores ; there is the First National City Bank with deposits of more than Rs 61 crores and there is the Chartered Bank with deposits of more than Rs 48 crores. Suppose a depositor wants to go to the National and Grindlays Bank and deposits his money. The deposit must earn interest. If you direct the Banks not to do business, where from are these Banks going to pay interest to the depositors ? This has never been clarified. It is impossible these days to talk about anything because everything is brushed aside on the basis of political slogan-mongering, this way and that way. Nobody talks about cooler judgment on the basis of the merits of the Bill. (*Interruption*) Immediately noise is made ; slogans are shouted. Somebody is called a reactionary ; somebody is called a progressive. (*Interruptions*) I can approach them through my voice; I cannot approach them through my reasoning. I am sorry they do not understand even now. What I want to say is that all the matters should be examined in a cooler manner, whether they will be legal or they will be tenable. To me, it looks that this will not stand the legal jurisdiction. (*Interruptions*) Why are you shouting ? Are you not in favour of nationalisation of foreign banks ? I want to know from the Communist party. I do not understand. They are trying to indulge in slogan mongering, to support somebody and not to support somebody else. Let them say so.

I would like to say that this is a very untenable situation. You cannot have a difference in the operation of banks as between nationalised banks and non-nationalised banks. The only tenable thing to do is to nationalise the foreign banks and other scheduled banks and to bring them all in the same purview.

15 hrs.

Apart from that, I have great apprehension that these foreign banks will attract a lot of depositors who are going to the nationalised banks. Therefore, with that kind of anomaly, with that kind of imbalance in our economy, we must outright nationalise foreign banks. Otherwise, there is no justification.

If this government claims that it has to bring into nationalisotion the banking institutions, it is a very welcome feature indeed. It should have been in a defferent way. That is a different matter. So far even by an accident, if socialism has received focus I welcome it wholeheartedly. But I would like to mention this. This is the time that the Government has to take a decision. Otherwise the Government will not be able to keep the foreign banks outside the purview of nationalisation. It will create a lot of repercussions. Therefore these banks should be brought into the purview.

SHRIMATI SARDA MUKERJEE : I have an amendment on this clause.

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : क्लाज़ 2 में मेरे दो एमेंडमेंट्स हैं, नम्बर 45 और 361। इन दोनों को मैं मूव करता हूँ। दोनों का मतलब यह है कि फारेन बैंक्स जोकि इस बिल के दायरे से बाहर रखे गए हैं, उनको बाहर न रखा जाए। इसका कारण यह है कि जब हमें आजादी नहीं मिली थी तभी से इंडियन कैपिटल और फौरेन कैपिटल का झगड़ा शुरू हो गया है। इंडियन कैपिटल समझता था कि आजादी के बाद जब फौरेन कैपिटल चला जाएगा तब जो रिक्तता पैदा होगी, उसकी पूर्ति इंडियन कैपिटल करेगा। लेकिन आजादी के बाद इंडियन कैपिटल और फौरेन कैपिटल मिल गए और दोनों ने मौनोपोली कायम की। फारेन बैंक्स को अगर आप छोड़ देंगे तो उन्होंने जो मौनोपोली बना रखी है, उसको बनाये रखने का रास्ता आप रहने देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि फौरेन बैंक्स को भी इस बिल के दायरे में लाया जाए।

दूसरा एक मेरा प्वाइंट और है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या नहीं। मुझे पता नहीं कि इंडियन बैंक्स को अगर नेशनेलाइज किया जाता है और फारेन बैंक्स को छोड़ दिया जाता है तो इससे कोई डिसक्रिमिनेशन होता है या नहीं। कहीं इस प्वाइंट को लेकर भी इस

बिल पर धक्का न आए, इस वास्ते भी यह जरूरी है कि फारेन बैंक्स को भी इसके दायरे से भी बाहर न रखा जाए।

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : The Government will have about 85% of the deposits of banking sector under their control. That leaves 15%. My colleagues have spoken before me asking for nationalisation of the remaining sector of the foreign banks and the smaller banks. It is such things which have unfortunately created the conditions that despite the Licensing Committee and the industrial policy resolution an uneven and unbalanced development has taken place. To-day we are shouting about the monopolies and so on. It is not difficult for some one who wants to evade the control in the banking sector over deposits of more than Rs. 50 crores, to have a number of small banks. Therefore, there may be a lot of things going on, which we would like to avoid.

The second thing is that as for as foreign banks are concerned, it is rather unfair that we should get our banks nationalised but leave the foreign banks scot-free to do what they like. Shrimati Tarkeshwari Sinha who has spoken before me has brought this out very clearly and I do not think that I need add to it. Therefore, I would like to join the hon. Members who have spoken before me and say that in clause 2 we should define the term 'banks' in such a way that it will extend to foreign banks also so that the foreign banks also should be nationalised.

It is true that there has been at least one foreign bank which has been indulging in nefarious types of activities, and that was a bank which was located at Calcutta. If I name it, my hon. friends opposite might have some susceptibilities, and so, I shall not name it.

SHRI NAMBIAR : Let her name it.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : We all know what happened in regard to the Bank of China.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : We only demand that the report of that inquiry should be published.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : I think he can make that demand to Government.

SHRI P. RAMAMURTI : She may also join us in making that demand.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : I do not thereby imply that all banks are working in that kind of way, but I do not see the validity of the arguement that there will be international repercussions or that it will affect our foreign trade. Our banks can carry on foreign trade operations just as well as Grindlays or the Chartered Bank or any of these other foreign banks.

I would request Government to consider the large number of Members on both sides who are in favour of the nationalisation of foreign banks also. If social control and nationalisation of banking has been accepted as the policy of Government, then it should extend to the entire banking sector.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, इस क्लाज दो पर कोई लम्बा चौड़ा संशोधन न देकर मैंने सिर्फ एक शब्द को हटाने के बारे में संशोधन दिया है। मैंने "नाट" शब्द को हटा देने की मांग की है। इसमें यह है :

> "Banking company does not include a foreign company within the meaning of section 591 of the Companies Act, 1956".

मैं चाहता हूं कि सिर्फ नाट शब्द को हटा दिया जाए। इसका मतलब यह होगा :

> "does include a foreign company...."

इसके बाद फिर दूसरा है बी में।

प्रधान मंत्री जी ने इस बिल पर जो तर्क दिये हैं, उनको पूरी तरह से सुनने के वाद और इस बिल को पेश करते हुए और बाद में विधि मंत्री जी ने जो तर्क दिये हैं, उनको भी सुनने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि एक भी माननीय सदस्य अपनी राय बदलने में असमर्थ हुआ होगा और उसको तसल्ली हुई होगी कि यह कारण है कि जिसकी वजह से विदेशी बैंकों को छोड़ दिया गया है और ऐसा करके अच्छा ही किया गया है। मुझे शक है कि प्रधान मंत्री खुद भी अपने तर्कों से सहमत हैं जो उन्होंने दिये हैं।

[श्री भोगेन्द्र झा]

जो बातें कही गई हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरा निश्चित विश्वास है कि अगर आप ने दूसरे बैंकों को छोड़ दिया तो जिन बैंकों का आप राष्ट्रीयकरण करेंगे वे बैंक भी नाकाम साबित होंगे। जैसा अभी अधिकांशत: पब्लिक सैक्टर में होता आ रहा है कई हमारे अफसर हैं जो दोहरा मुशाहरा पाते हैं, एक तो प्राइवेट पूंजीपति से, प्राइवेट कारखाने वाले से और दूसरे इन राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों से। वे हमारे इन पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज को सैबोटाज करने का काम करते हैं। यहां भी वे हमारे सरकारी प्रतिष्ठानों के अफसरों को, हाकिमों को और हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को सैबोटाज करेंगे और जो भ्रष्ट अफसर हैं उनका वे जाबे इस्तेमाल करेंगे। तब उस ्वस्था में हमारे दायें बाजू के जो सदस्य हैं उनको यह कहने का मौका मिलेगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक नाकाम साबित हुए हैं।

कल श्री कृष्ण मेनन ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। उस पृष्ठभूमि में मैं समझता हूँ कि इन बैंकों को छोड़ने का मतलब है कि जो आशा जगी है, उस आशा पर अभी वज्रपात होने वाला है। ये जो बैंक आप छोड़ रहे हैं, ये जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है उनको भ्रष्ट करेंगे। इस वास्ते इन बैंकों को छोड़ा नहीं जाना चाहिये। जान बूझकर खतरा मोल लेना ठीक नहीं है।

जो तर्क इसके पक्ष में दिये गए गये हैं, उन पर मैं जाना नहीं चाहता। कल मुझे भ्रम हुआ था उसको लेकर जोकि कांग्रेस के बारह सदस्यों ने दिया था। अभी तारकेश्वरी सिन्हा जी ने कहा है कि उसको कूलर मोमेंट में किया जाए। अभी गर्मी अधिक है। ठंडा होने पर किया जाए। मुझे शक है कि वह अभी विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहती नहीं हैं। वह "कूलर मोमेंट" पर जोर दे रही हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह हाउस एयर कन्डीशंड है। इसमें कर लिया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा : अगर यह मामले को टालने का बहाना हो, ता मैं नहीं कह सकता हूं।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन वह अमल में भी अच्छा साबित हो, इसके लिए यह जरूरी है कि को-आपरेटिव बैंकों को छोड़कर देशी और विदेशी सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इससे पूंजीवादी व्यवस्था पर भी कोई चोट नहीं पड़ती है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण के द्वारा हम आम लोगों द्वारा जमा रुपये को ले रहे हैं और जिन लोगों ने पूंजी लगाई है और जो उसका सैंकड़ों गुना लूटकर ले गए हैं, संविधान के मुताबिक हम उनको कम या ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं।

इस दृष्टि से यह कोई समाजवादी कदम नहीं है। अगर प्रधान मंत्री यह दावा करती हैं, या अगर उन्हें यह भ्रम है, कि यह एक समाजवादी कदम है, तो वह गलती पर हैं। इससे छोटे और मझोले पूंजी वालों को ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि उन्हें इस समय इजारेदारों के कारण नहीं मिल रहा है।

अब तक हमारे देश में एक दोगले पूंजीवाद का विकास हुआ है। यहां पर राष्ट्रीय पूंजी का ठीक तरह से विकास नहीं हुआ है। विदेशी पूंजी और विदेशी इजारेदारी के साथ देश के इजारेदारों की सांठ-गांठ के कारण इस दोगले पूंजीवाद का विकास हुआ है। विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करके अण्डर-इनवायसिंग और ओवर-इनवायसिंग के जरिए विदेशी मुद्रा की चोरी का रास्ता खुला छोड़ देना देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा।

इसलिए मैं अपने संशोधनों पर आग्रह करता हूं और चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और सरकार अभी भी इस विषय पर विचार करें, अन्यथा उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि वे कोई समाजवादी कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने जो कदम उठाया है, उससे देश में कुछ आशा उत्पन्न हुई है और वह जायज़ आशा है। लेकिन अगर विदेशी बैंकों को छोड़ दिया जायेगा, तो उससे एक संकट पैदा होगा और यदि संकट पैदा होगा, तो देश चुप नहीं रहेगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा और समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जोरदार संघर्ष करेगा।

इसलिए संघर्ष के दूसरे दौर का इन्तजार किये बिना सरकार को देशी और विदेशी सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। आज श्री मोरारजी देसाई को जाना पड़ा है, जिसकी हमें खुशी है, लेकिन कल श्रीमती इंदिरा गांधी के जाने के लिए हमें दूसरा धक्का न लगाना पड़े।

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): To what extent, the exclusion of foreign banks from the purview of this Bill will be in conformity with the Constitution is a matter that has to be ultimately decided by the Supreme Court on the basis of the evidence, material and other things available with Government. The hon. Prime Minister yesterday gave certain reasons why foreign banks are exeluded from the purview of the Bill. So far as these reasons are concerned, I am not going to say anything; we take it that the reasons are valid. But my difficulty is that in undertaking the connotation that has to be given to the expressions foreign bank' and 'Indian bank' there are certain implications in relation to a nationalisation measure. Today we have read in the newspapers that some London people have brought it to the notice of Government that 95 per cent of the shareholders of the Allahabad Bank which is being nationalised under this Bill are British nationals and they should be compensated in sterling. In categorising a bank as foreign bank, we have to go not exclusively by the place of incorporation. The place of incorporation can be a consideration in such economic measures though not the exclusive one. Here is a case of the Allahabad Bank which is obviously incorporated in India but the majority of the shareholders are Britishers. In the reverse situation, it would be conceivable—of course it is only academic now—that there may by a foreign bank which might have been incorporated in a foreign country but most of its shareholders would be Indians. In such a situation, how far it is convenient and consistent to keep such a bank outside the purview of the Bill is a matter I would like Government to consider.

Banking has so many operations-deposit operation, lending operation, etc. To what extent incorporation outside India can stop the Government or Parliament from legislating a foreign bank? Every sovereign country has a right over its territory. To what extent is it permissible for the Government to control the lending or deposit operations of a foreign bank in India? This question has to be examined. It is a foreign bank but its operations are in India. We have made some provisions in this Bill about banks operating in foreign countries. We have given some concessions to the foreigners. Therefore, the extent to which we have rights to regulate the undertakings of foreign banks should be considered and once again I request the Government to consider that suggestion.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, क्लाज़ 2 में मेरा संशोधन संख्या 106 इस प्रकार है :

Page 1, line 10,—

for ' "banking company" does not include a foreign company'

substitute-

' "banking company" includes both indigenous and foreign company'

मेरा संशोधन संख्या 107 इस प्रकार है :

Page 2—,

for lines 1 to 5, *substitute.*

'(b) "existing bank" means a banking company both indigenous and foreign specified in column 1 of the First Schedule with the present deposits as shown in the return as on the last Friday of June, 1969'.

[श्री शिव चन्द्र झा]

मोटे तौर पर मेरे संशोधनों का मतलब यह है कि देश में छोटे, बड़े और विदेशी, जितने भी बैंक हैं, उन सब को ले लिया जाए। जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध हैं, प्रधान मंत्री ने तर्क दिया कि विदेशी बैंकों का सारी दुनिया में बड़ा नेटवर्क है, उन की बहुत सी शाखायें हैं, उनके पास नो-हाऊ है, जो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए यदि हम उनको लेते हैं, तो हम उन्हें ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं। जब मैंने इस तर्क को सुना, तो मुझे हैरानी हुई कि शायद जब इतना बड़ा विधेयक लाया जा रहा है, तो राष्ट्रीयकरण बैंकों का जो दुनिया में हुआ, उसका इतिहास इन्होंने कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं किया। बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसमें विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ जिसमें हिन्दुस्तानी बैंकों भी आते हैं। उसके बारे में तो कहा गया लेकिन एक दूसरे मुल्क, बर्मा से भी छोटे और हिन्दुस्तान से भी छोटे मुल्क टैंजिया ने राष्ट्रीयकरण किया, उसमें उसने विदेशी बैंकों का, और हिन्दुस्तानी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया। उसमें हिम्मत थी। उसके पास वह नो हाउ नहीं था, उसके पास उतना नेट वर्क नहीं था उसके पास इतनी स्किल नहीं था, लेकिन उसके पास हिम्मत थी राष्ट्रीयकरण करने की ओर उसने कदम उठाया। हिन्दुस्तानी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण उसने किया बावजूद नो हाउ न होने के और सुविधाएं न होने के भी। तो टैंजिया जैसा मुल्क हिम्मत कर सकता है तो हिन्दुस्तान जैसा इतना बड़ा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी परम्परा रही है, वह इनका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता, यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने इसके ऊपर ठीक से गौर नहीं किया—विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में और दूसरे शब्दों में मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद इसमें भीरुता तो नहीं है। क्या प्रधान मंत्री जी घबराती तो नहीं हैं, डरती तो नहीं हैं कि इनका राष्ट्रीयकरण करेंगे तो शायद हमारा स्वागत न हो दुनिया के दूसरे मुल्कों में यह बात भी हो सकती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुताल्लिक भी यह है कि आज से वर्षों कब्ल दादाभाई नौरोजी ने एक बड़ी भारी किताब लिखी आन प्राप्रर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी चिन्ता, उनकी तकलीफ उनका दर्द यह था कि हिन्दुस्तान से एकोनामिक ड्रेन होता है। विदेशी लोग और विदेशी हुक्मरां हिन्दुस्तान का शोषण करते हैं। वह शोषण विदेशी बैंकों से अभी भी चल रहा है। यह विदेशी बैंक जो हमारे हिन्दुस्तान में काम करते हैं उनके जरिये करोड़ों रुपये मुनाफे के कमाये जाते हैं और हिन्दुस्तान से बाहर भेजे जाते हैं। करोड़ों रुपये का मुनाफा करके उसे बाहर भेजना दादा भाई नौरोजी के शब्दों में हिन्दुस्तान का खून हिन्दुस्तान से बाहर भेजना है। यही विदेशी बैंक कर रहे हैं। इसलिए लाजिमी हो जाता है कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान की जितनी भी ट्रेड होती है, हिन्दुस्तान के मेहनतकश का जो खून है उसको बाहर न भेजा जाय, उसका ड्रेन न हो। उसके ऊपर रोक लगाना हमारा पहला फर्ज है। इसलिए विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण लाजिमी हो जाता है। इन सब बातों पर प्रधान मंत्री ने गौर नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि विदेशी बैंक भी इसमें आ जायं।

दूसरी बात—पचास करोड़ से नीचे जो देशी बैंक हैं उनको भी ले लेना चाहिए। उन का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। जैसा कि बताया गया दस करोड़ के भी बैंक हैं, 5 करोड़ के भी बैंक हैं। ठीक है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि छोटे बैंक जो हैं, जब बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो उनका अमलगमेशन मैनेजमेंट के ख्याल से होना लाजिमी हो जाता है। तब हम एफिश्येंटली वह एक नया नक्शा जो आने जा रहा है उस पर काम कर सकेंगे।

इसलिए यह इनएविटेबल हो जाता है, लाजिमी हो जाता है, जो कदम आप ने उठाया उसका दूसरा कदम कि है आप उनको भी एफिश्येंटली चलाएं और उन पर भी कब्जा करें। इसलिए छोटे बैंक जो हैं हिन्दुस्तान के देशी उनको भी और विदेशी बैंकों को भी राष्ट्रीयकरण करें। तभी जाकर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो देश में है उस पर सरकार का कब्जा होगा और तभी जो पूंजी है, पैसा है, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करने योग्य हालत में होगी ताकि योजनाओं को सरकार आगे बढ़ा सके और जिस संकट में हमारी अर्थ-व्यवस्था है उससे निकल करके जो हमारी मंजिल है, जिस ओर हमारा राष्ट्रीय कारवां चल रहा है—समाजवाद, उस मंजिल पर हम जायं और आम जनता की हालत अच्छी हो। यही मेरे दो संशोधन हैं जिन को मैं आप के सामने रखता हूं।

SHRI P. C. SETHI : As far as my amendment is concerned it is only a verbal amendment substituting the word "a" in place of "the".

SHRI S, M. BANERJEE *rose*—

MR. CHAIRMAN : Before Shri Benerjee speaks I want to draw his attention to the fact that we have a number of amendments and if he takes a long time repeating the same arguments we will not be able to conclude this. Please do not repeat the arguments.

SHRI S. M. BANNERJEE (Kanpur) : Sir, I will speak only on my amendments to clause 2.

सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट नम्बर है 154 और 155। 154 में यह कहा है कि लाइन 10 और 11 का सब्स्टीट्यूशन इस प्रकार हो। बिल में यह दिया है :

> "Banking company" does not include a foreign company within the meaning of section 591 of the Companses Act, 1956 ;"

मेरा संशोधन यह है कि :

> "'Banking company" means a banking company as defined in section 5 (c) of the Banking Regulation Act, 1949 but excludes co-operative banks."

अब मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूँ कि आखिर बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट 1949 का सैक्शन 5 (सी) क्या है :

> "Banking company" means any company which transacts the business of banking in India".

तो मेरा संशोधन यह है कि सभापति महोदय, कि कोई भी बैंक चाहे विदेशी हो या देशी हो या स्वदेशी उसका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। जब एक दफ़ा राष्ट्रीयकरण की बाढ़ आई है इस देश में और प्रधान मंत्री जी ने एक हिम्मत कर ही लिया...(व्यवधान)...सभापति महोदय, मैं बिल का संशोधन चाहता हूँ, माननीय सदस्य का संशोधन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वह ख्वामख्वाह नाराज हैं।

मैं यह कहना चाहता था कि आज जब प्रधान मंत्री महोदय ने हिम्मत से काम ले ही लिया और जब सारे देश के बैंक कर्मचारियों ने और मेहनतकश लोगों ने जो मेहनत करके खाते हैं, दूसरे की कमाई नहीं खाते हैं, सब ने इसका स्वागत किया तो एक दफा बहती गंगा में उन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो जाय और मैं इस बात को कहूँगा और उनसे निवेदन करूंगा कि अब की मर्त्तबा कुछ इने गिने लोग इस सदन में भी हैं वह काफी योग्य हैं और काफी एजूकेटेड भी हैं, जो इसके विरोध में हैं लेकिन उनसे तो गुणानन्द ठाकुर जी अच्छे हैं जो इसकी सपोर्ट तो कर रहे हैं। ज्यादा लिखने-पढ़ने से अगर यह असर होता हो कि नेशनलाइजेशन न हो तो मैं समझता हूं कि वह गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज मौका है, इस सदन में जब कि एक मुट्ठी भर मामूली लोगों को छोड़ कर जिनके पीछे कोई जनता है नहीं, सारा देश इसका स्वागत कर रहा है तो इन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। मेरी अमेंड-

[Shri S. M. Banerjee]

मेंट मंजूर कर ली जाय। जय प्रकाश जी की बात कही गई है। लेकिन जय प्रकाश जी की हर बात हम लोग नहीं मानते हैं, अगर आप मानें तो दूसरी बात है...(**व्यवधान**)...एक अजीब हालत है कि आप लोगों की पार्टी इधर नाभा की महारानी का समर्थन कर रही है, राजाजी कहते हैं कि उनको मेरा समर्थन है, लेकिन उधर आपने श्री देशमुख को अपना कैंडीडेट खड़ा कर दिया है।

सभापति महोदय, यह मौका आ गया है जबकि देश के तमाम बहाव को देखकर, जनता की आवाज को देख कर, सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इन बैंकों के जो काम करने वाले कर्मचारी है, उनके हालात को सुधारा जाय, तब ही आज तक उनका जो शोषण हुआ है, वह दूर हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा संशोधन मंजूर किया जाय।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : सभापति जी, मैं दो रोज से बैंक नेशनेलाइजेशन के सिलसिले में अपने साथियों की काफ़ी तकरीरें सुन रहा हूँ। जहां तक इसकी मुखालफत का सवाल है जो कैपिटलिस्ट—निजाम के हामी हैं उनकी तरफ़ से मुखालफत करने की बात समझ में आती है, मगर जो लोग समाजवाद के हामी हैं, जो लोग यह चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिये, जब उनकी तरफ़ से मुखालफत की बात सामने आती है, तो मुझे एसा महसूस हुआ कि क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ नहीं रहा तो उन्होंने पार्टी को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया।

मुझे मधु लिमये जी माफ़ करेंगे, उनसे मुझे यही उम्मीद थी कि वह ऐसी ही तकरीर करेंगे, लेकिन अपने मौअज्जिज साथी द्विवेदी जी और आचार्य कृपलानी जी से मैं यह तवक्को नहीं करता था। उनसे तो मुझे यह उम्मीद थी कि बैंक नेशनेलाइजेशन का जो बिल आया है उसके सम्बन्ध में कोई खास बात रखेंगे...

SHRI ABDUL GANDHI DAR : Sir, on a point of order. You have never allowed us so speak generally. But he is doing that while speaking you a asked us not to bring in politics. But what is he talking about except on the general question ? And yet you are permitting it.

श्री मु० अ० खां : वकील बनर्जी साहब के आप काफी बुजुर्ग हो गये हैं, आपकी समझ में ऐसी बात नहीं आयेगी, इसलिए आप तशरीफ़ रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।

सभापति जी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि इंदिरा जी बाज़ी मार ले गईं—मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने 20 साल से जो कांग्रेस इधर-उधर भटक रही थी...

SHRI S.K. TAPURIAH (Pali) : Let him speak on the clause or on the amendments.

But he is now making a general speech.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Why did you call him ?

श्री मु० अ० खां : मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं दी है।

SHRI D.N. PATODIA (Indore) : What he is speaking is not about any amendment moved by anybody.

15.34 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SHRI S. K. TAPURIAH : Sir, on a point of order.

SHRI RANDIR SINGH (ROHTAK) : Sir, the hon. Member be allowed to speak.

SHRI S. K. TAPURIAH : We are on clause 2 now. The hon. Member has not given notice of any amendment. What he is speaking does not go anywhere near clause 2. Now, can anybody speak without moving any amendments ? (*Interruption*).

श्री बेणी शंकरशर्मा (बंका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । आपके पहले सभापति जी उन्हीं लोगों को, जिन्होंने अमेंडमेंट्स दिए थे क्रम से बुला रहे थे । मेरी प्रार्थना है कि आप भी जिस क्रम से जिन लोगों ने संशोधन दिए हैं उसी क्रम से उन लोगों को बुलायेंगे ।

श्री मु० अ० खां : मुझसे पहले जिन लोगों ने अमेंडमेंट्स दी हैं, उनको भी बुलाया गया है और जिन्होंने नहीं दी हैं, उनको बुलाया गया है ।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, यह समझने की कमी है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Usually the procedure that we follow is that after the amendments are moved, first those who have moved them get an opportunity and then those who are not in agreement with them get some opportunity to oppose them. A few more hon. Members who have moved amendments to clause 2 still remain. First I will give them a chance and than I will give you an opportunity.

श्री मु० अ० खां : आप मेरे बाद उनको मौका दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको फिर मौका देंगे । Was he called by the Chair ?

श्री मु० अ० खां : मुझे बोलने के लिए एलाउ किया गया है । मेरी कोई अमेंडमेंट् नहीं हैं । आप मेरे बाद उनको बोलने का मौका दीजिए ।

श्री मधु लिमये : क्लाज-बाई-क्लाज कंसीड्रेशन के लिए निश्चित समय है । इस समय 500 अमेंडमेंट्स विचाराधीन है । जिन्होंने मेहनत करके संशोधन दिए हैं, उनको आप मौका दें, यहां ऊट पटांग भाषण करनेवालों को... ...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, I want your ruling whether the word "*utpatang*" is parlimentary.

श्री मधु लिमये : आप क्यों बोल रहे हैं, मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं । जो ऊट-पटांग बोलते हैं, उनके लिए कह रहा हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Such expressions should be avoided.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, I am impatiently waiting for your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has agreed to avoid such expressions.

श्री मधु लियये : अरे भाई, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि चौधरी साहब कभी ऐसा नहीं बोलते । इस समय 500 अमेंडमेंट्स आपके सामने हैं । क्या आप जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी हैं, उनको मौका देंगे या जिन्होंने संशोधन नहीं दिया है, उनको मौका देंगे । अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर बाद में गिलोटीन न किया जाय ।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : We have got our amendments. Will you allow us to speak or not ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume you seat. This is not the way ?

SHRI DHIRESWAR KALITA : This is the way. You want it this way.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat.

I entirely agree that our time is limited. I do not want to guillotine the clause because they are important. I will give those who have taken pains to amendments an opportunity to make their brief submissions as possible. Normally we do not allow those who want to oppose until all the amendments concerning a clause are finished but as the Chair has permitted him to speak let him conclude.

श्री मु० अ० खां : मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने बावजूद इन लोगों के एतराज के मुझे बोलने का मौका दिया ।

[श्री मु० अ० खां०]

मैं इस सदन के सीनियर और बुजुर्ग मैम्बरों से यह उम्मीद नहीं करता था कि हमारी पार्टी के अन्दर के जो मामलात हैं उनको क्रिटिसाइज किया जायेगा बल्कि मैं उम्मीद करता था कि कृपलानी जी और द्विवेदी जी की तरफ से इस बिल पर कोई खास चीजें आयेंगी। लेकिन मैंने देखा कि क्या बंगलौर में हुआ, क्या वर्किंग कमेटी में हुआ और क्या पार्लेमेंटरी बोर्ड में हुआ यही बातें इस सदन में रखी गई। और चीजों का इस सदन से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह से वक्त खराब किया गया...... ...(**व्यवधान**)......बीस साल से कांग्रेस जो इधर से उधर भटक रही थी, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने यह बहादुराना कदम उठाया और मुल्क को दिखा दिया कि समाजवाद का जो नारा सबसे पहले कांग्रेस ने लगाया था उसकी पूर्ति की गई है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, आगे भी हमको बहुत कुछ करना है। इसी बात से हमको तसल्ली नहीं कर लेनी है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे निजाम के ऊपर जो नौकरशाही का जाल बिछा हुआ है, हमको डर महसूस होता है कि जिस तरह से नौकरशाही ने पब्लिक सैक्टर को बर्बाद किया है और आज तक हमारे मंत्री इस काबिल नहीं बन सके हैं कि उस जाल को काट सकें, कहीं वही जाल बैंकों के ऊपर भी न छा जाये। मैं चाहता हूं कि नौकरशाही से इन बैंकों को बचाया जाये।......(**व्यवधान**)...... इंटरप्शंस की वजह से मुझे वह नहीं कहने दिया गया जोकि मैं कहना चाहता था, बहरहाल मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : As has been pointed out by the hon. Members, we have got a time-limit fixed. So, I would appeal to all the hon. Members—I want to give an opporunity to all the Members who have moved amendments—to speakon clause 2 and the amendment that are before the House and that no extraneous matters should be brought in.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I have moved an amendment to clause 2 that instead of "rupees fifty crores", it should be put as "rupees twenty-five crores". On the point whether the foreign banks should be nationalised or not, I agree with those who have said they have got to be nationalised. In fact, I am of the opinion that if banking industry is to be nationalised......

SHRI K. NARAYANA RAO : On a point of order, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it not admissible ? What is your point of order ?

SHRI K. NARAYANA RAO : When such a senior Member speaks, I do not unnecessarily interrupt. Let me make myself clear about that. About this amendment, he wants to make a change from "rupees fifty crores" to "rupees twenty-five crores". This amendment is meaningless so far as clause 2 is concerned. Let me read clause 2. It says :

> '(b) "existing bank" means a banking company specified in column 1 of the First Schedule......'

That is the operative part of that particular sub-clause. Then there follows the descriptive part, that is, about rupees fifty crores. If you want to reduce the amount to rupees twenty five crores, then the entire Schedule goes. You have to bring in so many unspecified banks into the picture. Therefore, such an amendment cannot be moved.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are certain principles regarding legislation and about admissibility of amendments to clauses. I may point out to you that if an hon. Member feels that an amendment is called for here, naturally, a consequential amendment will have to be moved to the Schedule. Therefore, I cannot shut him out on this ground.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : One reason why I want to expand the scope of this Bill is this. The purpose of nationalisation is to get more res ources. Now if

all the banks were nationalised, certainly there will be more resources If some are nationalised, resources will be smaller. Now, banks with deposits over, Rs. 50 crores are taken, these Rs. 2800 crores are the additional amount which will come into the hands of the Government now 25% is already in Government securities. Of this 59% is already in State, Central Government securities and 20% or more are in State Government securities on loans and advances have absorbed 2000/-. Therefore, out of these 2800 crores the Government have got at their disposal practically 80%. Now only 20% remains. It would come to Rs. 600 crores. Therefore, by this measure you will be able to get only Rs. 300 crores. By nationalising the foreign banks also you will get more money. That is why I said 'bring the 5 crores also and reduce the limit of exemption.' I do not think that other banks are not capable of making much mischief. I may tell you, there is one bank with headquarters at Hyderabad which gave 1 crore guarantee to Dharma Teja. At that time the Government of Adhra Pradesh refused to give him further guarantee. I have got so many telegrams the from employees of the Andhra Bank that it should be nationalised. It is necessary to increase the scope of this Bill. That is the reason why I would amend Rs.50 crores and have Rs. 25 crores at the exemption limit. I will be very glad if all the banking institutions except the small ones can be nationalised.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): My amendment is confined to bringing within the scope of the operation of this Bill the foreign banks. Many points have been made so far, I am not going to repeat those arguments. I would like to point out that this Bill seeks to give the most favoured nation treatment to foreigners. Foreign nationals who do not belong to this country are given a treatment more favourable than that given to any national in this country. I do not think that either our Constitution or our national self-respect can permit that a business which an Indian national cannot do in this country should be open to a foreign national. This is from the point of view of our own national self-respect. I do not want to enlarge the scope of my arguments.

Secondly, I am not at all convinced by arguments of the Prime Minister that since some of these banks are helping us to finance exports and imports, they must be allowed to operate outside the scope of this Bill. I cannot conceive that a Government which is going to take into its own hands the management of nearly 82 per cent of the entire banking finance of this country is not capable of entering into arrangements with certain foreign banks in foreign countries to assist in the operation of financing exports and imports or is not capable of having its own financial institutions to do this work. It passes my understanding.

Therefore, on any count, these foreign banks do not deserve this special favoured treatment, and they must be taken over. Otherwise, they are capable of a tremendous amount of mischief particularly in regard to sequestering the foreign exchange we earn. In this, these foreign banks play a very prominent role in helping some of the anti-social and anti-national elements who have made it their life's job to sequester and keep in secret the foreign exchange resources of this country.

Without expanding my arguments, on these two counts alone, the foreign banks must be included within the scope of the Bill. I do not know the legal implications of doing it, but definitely they must be included in the Bill.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मान्यवर, क्योंकि यह राष्ट्रीयकरण की बात है इसलिए मैं राष्ट्रीय भाषा में बोलना चाहता हूं। वैसे इसमें भी बहुत गलती हैं, अगर बोलने में मुझ से गलती हो तो उसका ध्यान न किया जाये।

मेरा जो संशोधन है वह मैं संशोधन में संशोधन करना चाहता हूँ। थोड़ी गलती हो गई है, शायद प्रिंटिंग में। मैं पढ़ देना चाहता हूं :

> "existing bank" means a banking company incorporated in India or outside excluding Industrial Development Bank of India, the Reserve Bank, the State Bank of India, and its subsidiaries functioning in the country, co-operative banks or Banks

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

carried and managed by public bodies like municipality'.

इसके बाद जो है :

"Are excluded from this dfincition." यह जरा रिपीटीशन है इसलिए मैं इसको निकाल देना चाहता हूं। आपने चूंकि पहले से सतर्क कर दिया है कि इस बारे में ज्यादा भाषण नहीं होना चाहिये इसलिए मैं दो, एक बात ही सिर्फ कह देना चाहता हूं।

अगर सचमुच हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में आर्थिक समबल है उसको देश के हित में काम में लायें तो इस अधूरे बिल से वह काम पूरा होने वाला नहीं है। थोड़े लोगों को हम छोड़ देंगे वह अपने मन के मुताबिक देश को लूटेंगे और हम सिर्फ एक हिस्से को अपने हाथ में पकड़ कर आगे चलना चाहें तो यह नीति कामयाब होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह साफ़ हो जाये कि हम क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता चलें, ऐसी बात अगर आप इस विधेयक में कहते तो हमको आशा हो सकती थी कि एक, दो महीने बाद फिर सरकार कोई स्ट्रैप लेने वाली है फ़ौरेन बैंक्स को लेने के लिए। आप ने यह भी नहीं कहा बिल में कि हम ऐसा अधिकार ले रहे हैं कि इसके बाद जो बैंक्स रह गये हैं उन को भी लेंगे। आप सिर्फ इतना करके बन्द कर देना चाहते हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने भी बैंक्स हैं, फ़ौरेन या देश के जो बैंक रह गये हैं उनको सरकार ले। आप को मालूम है कि ये बैंक्स जो रह गये हैं वे कितने रुपयों का कारोबार कर रहे हैं? हमारे दोस्तों ने बताया कि देश को हानि पहुंचाने के लिए इनके पास बहुत स्कोप रहता है, सुविधा रहती है।

कल हमारे ला मिनिस्टर जवाब देते वक्त बड़ी घबराहट में थे। उन्होंने कहा कि कोई कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनके पास नहीं पहुंचा। मुझे मालूम नहीं है कि उनके ख्याल में कांस्ट्रीक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। लेकिन यह एक कांस्ट्रीक्टिव सजेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि अगर कोई रचनात्मक बात उनकी समझ में नहीं आती है तो वह इसको समझकर मंजूर करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are several amendments, differently worded but meaning the same. If I were to permit Members to speak on them, the substance being the same, everybody will have to make the same statements and repeat the same thing. He has made one specific point about one bank. Mr. Dwivedy has made the point about the foreign bank. Members may speak if they have some new points.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : My amendment to clause 2 is simple. When I glanced through this Bill I wondered whether this Bill was drafted in a hurry or with no definite purpose. They have not kept scope for re-thinking and kept no provision so far as the foreign bank is concerned. As it is they cannot acquire the foreign banks and this Bill does not leave any scope in the future also. In case there will be another inner conflict in the Congress and they want to acquire foreign banks also, they have to bring a separate Bill. Therefore, I have moved on amendment No. 203 to clause 2 which says that a banking company does not include a foreign company. I have said 'includes'. After the word "Schedule" in page 2, line 2. I have inserted "and any such other banks" so that foreign banks will also come under that provision. Government should have acquired foreign banks first as in Burma where they did so. Because of unhealthy speculation and for lot of bad investment in foreign banks it was taken over. Those foreign companies carry on trade get a lot of money from the foreign banks where the deposits are of the people of the soil. Another advantage in acquiring foreign banks is that you have to pay a very nominal compensation because you do not pay compensation to the shareholders. Since you take over only a branch of a foreign bank. Therefore, it would have been of great advantage to the nation and also to the economy of the country if they had acquired these foreign banks also. I would still suggest that even if they do not accept

[Shri S. Kundu]

my amendment they should bring in another amendment or even a Bill soon to acquire these foreign banks.

16 hrs.

I have given another amendment which is to the effect that Rs. 50 crores should be reduced to Re. 1 crore. I do not want to dilate on this matter. If you limit it to Rs. 50 crores and over, as Shri Viswanatham said, you will leave the banking business to many undesirable hands.

The last point that I wish to make is this. While we might acquire these banks, we must create a banking bias in the minds of the people. If you do not do that, I think the entire purpose of this Bill will be defeated and the money cannot reach the agriculturists and the small scale industries. Today, the Sahukars charge the the poor people in the villages and others an interest of 70 per cent for the money they lend to them in the villages. Therefore, these nationalised banks should not become new Sahukars in place of the existing Sahukars. Therefore I would appeal to the Law Minister to find out some provision to see that the idea of banking is acceptable to a large number of depositors and creditors in this country.

SHRI JYOTIRMOY BASU *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will call you after Mr. Nambiar.

SHRI JYOTIRMOY BASU : It is a joint amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What about Shri Dandeker's amendment ?

SHRI N. DANDEKAR : I am not pressing my amendment.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Sir, I wish to speak on my amendment, which is a joint one. I do not want to repeat the arguments of the hon. Members who have spoken earlier. The Government should have at least told the House as to how these foreign banks are operating and why these foreign banks are not taken over. The only reason given by the Prime Minister is that foreign trade will not take place ; that is not understandable or acceptable, because, for the business of foreign trade, you could have the mechanism of our own banking.

We also want to know what exactly stands in the way. Is it their point that if you take over the foreign banks, it will involve foreign policy matters or it will involve our relations with other countries ? If that is so, let us know it. Therefore, I have specifically stated that certain banks should be taken over. Shri Kundu has asked for the removal of the words "does not". That means, you must include all the banks. That is a simple thing.

Therefore, when the Government have taken up the matter to such an extent, by bringing an ordinance, etc., they should take the whole country and the whole people into confidence and tell them that we are taking over the foreign banks as well. We have a right and have the necessity. That must be done. Otherwise, it does not cut any ice. That is my submission.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamand Harbour) : Sir, I rise in support of my amendment. Why I say that the foreign banks should be taken over is beause this country is losing to the tune of Rs. 400 crores or Rs. 500 crores in foreign exchange every year through underinvoicing and over invoicing and mostof the mischief is done by the foreign banks.

I will give one or two recent examples. There is the National and Grindlays Bank of Calcutta. If I remember aright, there was a man there called Mr. MacDonald who entered into a conspiracy by which they were remitting foreign exchange to Hong Kong in the name of a medical student who never existed.

SHRI D. N. PATODIA : Names should not be mentioned, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please avoid names.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I know whom they represent. *(Interruption).*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not bring in names especially because you have not given previous intimation.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Well, in that case, my name also need not be mentioned when you call me for the amendments. We cannot function like this, Sir. Now, if you really want to put an end, or at least a partial end to this danger of malpractices, which is robbing this country to the tune of thousands of crores of rupees in foreign exchange, you must take over the foreign banks. I will tell you of another bank, American Express. You can go and get foreign exchange through the touts by paying a commission. They will give you chits and you can get foreign exchange in any place in the world. Of course, you will get only a high premium over the correct value. You cannot control these things. Unless the banker is an Indian citizen and he is subject to Indian laws the man will do the misehief here, rob you and go abroad and hide himself. Like Mr. Dharma Teja the man will escape the law. Let Lord Mountbatten come here and pressurise our friends. They should toke over the foreign banks.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि सरकार ने 14 बैंकों को ले लिया और दूसरे बैंकों को छोड़ दिया। जब बिहार में सरकार ने जमींदारी अबालिशन कानून बनाया तो उसने दरभंगा महाराज की जमीदारी भी ले ली और जो एक बीघा, आधा बीघा और चौथाई बीघा जोतने वाले जमीदार थे उनकी जमीदारी भी ले ली। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि यह सरकार डिस्क्रिमिनेशन करने जा रही है क्योंकि उसने 14 बैंकों को ले लिया बाकी को छोड़ दिया, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस होनी चाहिये। जब आपने सबके साथ में न्याय करने का वादा किया था तब सब बैंकों को लेना चाहिए था। थोड़े से बैंकों को लेने का कोई औचित्य नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब चूंकि बड़े-बड़े बैंकों को ही लिया गया इसलिए इसका नतीजा यह होगा जिन लोगों का रुपया जमा है वे अब उस को छोटे बैंकों में ही जमा करेंगे। हम देखते हैं कि इस विधेयक के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि जितना काम हमको करना है उसके लायक हमारे पास रुपया नहीं है। अभी तो हमने केवल 27 अरब का राष्ट्रीयकरण किया है और कहा जाता है कि कुल 35 अरब रु० है। मगर इधर अखबारों को पढ़ने से मालूम हुआ कि कुल 43 अरब रु० जमा है। हमारा सारा काम 27 अरब रु० से पूरा होने वाला नहीं है। ऐग्रीकल्चर, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, एक्सपोर्ट, रेजिंग आफ एम्प्लायमेंट लेवेल, एनकरेजमेंट टू न्यू एंटरप्रेनर्स और बैकवर्ड एरियाज के डेवेलपमेंट के लिए हमको रुपया चाहिए। इसके लिए सरकार को रुपयों की सख्त जरूरत है। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि सरकार के दिमाग में दूसरे बैंकों की बात क्यों नहीं आई।

मैंने प्रधान मंत्री का भाषण सुना और मैं प्रधान मंत्री को हृदय से धन्यवाद कहिये या बधाई, देता हूँ। मैं तो कहता हूं कि हिन्दू शास्त्र के मुताबिक वह 100 वर्ष तक जिन्दा रहें क्योंकि उन्होंने यह बड़ा कदम तो उठाया। हमारे भाई कहते हैं कि यह सब कुछ झगड़े से हुआ। झगड़े से तो हमने राज्य लिया। क्या इसमें कोई बुरी बात है? जो झगड़ा नहीं करना चाहते थे। वे उधर बैठे हुए हैं। हमने झगड़े से राज्य किया और राज्य करना चाहते हैं। अगर हमारे यहां फिर झगड़ा होगा तो जो हमारे सिद्धान्तों पर चलेंगे वह रहेंगे, जो उन पर नहीं चलेंगे वह हट जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस का रगड़ा होगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं बतलाना चाहता हूँ कि गांधी जी ने नान-कोआपरेशन का मूवमेंट शुरू किया। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। वह लोग छंट गये और हम आगे बढ़ गये। जो लोग जेल जाने वाले थे वह जेल गए।

[श्री विभूति मिश्र]

आज हमारे यहां झगड़े से घबराने वाला कोई नहीं है। हम लोग रोज कसरत करते हैं जिस से बदन में ताकत आती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सभी बैंकों को ले क्योंकि जो काम हमारे जिम्मे है वह थोड़े से रुपय से पूरा नहीं होगा। मिसाल के लिए मैं बतलाऊं कि गण्डक प्रोजेक्ट रुपये के अभाव में दस वर्षों से मर रहा है। उसके लिए 50-60 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है। कोसी नहर के लिए और वागमती के लिए पूंजी चाहिये। यह रुपया कहां से आयेगा? अगर अपील की जाती है तो जितने धनी आदमी हैं वह बांड नहीं खरीदते हैं, सरकार को लोन नहीं देते हैं। अब जब सरकार बैंकों को लेने जा रही है तब यह लोग घबराते हैं। यह घबराने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो दुनिया में पैदा होता है वह दौलत लेकर नहीं आता है और जो मरता है वह दौलत लेकर नहीं जाता है। आखिर बीच में उनके पास दौलत कहां से आ जाती है। इसके माने हैं कि जो राज्य है, जो सरकार है, वह किसी को गरीब बनाती है और किसी को दौलतमन्द बनाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को उन का धन लेने का भी अधिकार है।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा पर अपने संशोधन को पेश करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक सदन के सामने पेश है, उसका स्वागत किया जाना चाहिये। जिस वातावरण में यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है उसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस के अन्दर झगड़ा होने से अगर अच्छी चीज निकलती है तो मैं चाहता हूं कि और झगड़े पैदा हों तो और भी बड़ी चीज निकले ताकि देश का फायदा हो।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी समाज की रचना पर बहुत जोर दिया है और बहुत सी दलीलें पेश की हैं। मैं समझता हूं कि उनके दिलोदिमाग में हिन्दुस्तान से गरीबी को मिटाकर समाजवादी समाज की रचना की बात अगर होती तो बहुत पहले वह इस प्रकार का विधेयक और इससे भी अच्छा विधेयक लाने की कोशिश करतीं। लेकिन उनके दिमाग में या कांग्रेस दल में कोई समाजवादी विचारधारा नहीं है। यह तो घटनावश एक चीज हो गई है। अगर ऐसा न होता तो अधूरे और आधे मन से यह बिल न लाया जाता। इसमें पचास करोड़ से ऊपर के जो बैंक हैं उनको लेने की बात आपने कही है। जहां तक फारेन बैंक्स का सम्बन्ध है उनको भी आपने छोड़ दिया है। इन दोनों के पीछे कोई तर्क मालूम नहीं होता। इससे यही पता चलता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो मर्ज हैं उनका इलाज निकाला जाए।

मैं चाहता हूं कि फारेन बैंक्स को भी लिया जाए और पचास करोड़ के नीचे वाले जो बैंक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : I have moved two amendments, one along with Shri Nambiar and several others, suggesting that all the major banks including foreign banks be taken over. Then, hearing Shri V. K. Krishna Menon the other day and also hearing some of the aboved apponents of Bank Nationalisation Bill, coming in favour of including the foreign banks as well, I felt that there may be some snag somewhere. Anyhow, I wanted to give the government full freedom of movement and, at the same time, open the vista much wider. Therefore, I have moved my two amendments. One reads : Page 1, line 10 omit "not" and the one says : after "specified" insert "and to be specified in futuree'. So, if and when the government wants to include all these banks, including foreign banks, they can without any new legislation automatically take them in.

Then I have suggested the substitution of Rs. 50 lakhs for Rs. 50 crores in the matter of deposits so that any bank of any fair size may be included in the list by executive orders and be taken over without any new legislation being brough in.

[Shri N. Sreekantan Nair]

In this base there is one aspect which I want to stress. If there is any discrimination, as has been pointed out by some hon. Members, and if it is considered to be a factor to strike down this Bill, by bringing in this clause or explanation we can automatically avoid it. At the same time, if the government have any specific purpose in excluding foreign banks, they can serve it by not taking them over.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जिस तरीके से और जिस परिस्थिति में यह बिल लाया गया है मेरी पार्टी ने उसका विरोध किया है। लेकिन चूंकि यह राष्ट्रीयकरण होने जा रहा है, इसलिए जो संशोधन सदन के सामने है कि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। अगर राष्ट्रीयकरण बैंकों का करना है तो सबसे पहले विदेशी बैंकों का होना चाहिए। अपने देश के सरमायेदारों या पूंजीपतियों के हाथ से सरमाया छीन कर दूसरे हाथ से विदेशियों के हाथ में अगर आप डालना चाहते हैं, तो यह गलत चीज होगी। प्रधान मंत्री ने कल विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किये जाने के बारे में जो दलीलें दी है, वे एक दब्बू तरीके की थीं। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर रखा है और साथ साथ वे विदेशों के साथ व्यापार भी करते हैं। यह सरकार नाटकीय ढंग से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है और समाजवाद का नारा लगाती है लेकिन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नही करती है। यह जो नारा लगाती है यह धोखामात्र है, यह एक पोलिटिकल स्टंट मात्र है। हमारी इकोनोमी के डिवेलेपमेंट के लिए और देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह जरूरी है कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो। इस वास्ते मैं कहूँगा कि अगर राष्ट्रीयकरण करना ही है तो सबसे पहले विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप करें। आप अपने पैरों पर खड़े हों। हम किसी के दबाव में न आएं। न अंग्रेजों के और न ही अमरीकियों के और न ही रूसियों के। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग क्या कहेंगे। हमारी अर्थ व्यवस्था क्या होनी चाहिए, यह हम स्वयं तय करें।

आप को तो मालूम ही है कि बैंक आफ चाइना ने कितना मिसचीफ किया था और बाद में जब हमने उसको पकड़ा तो उसमें कितना गोलमाल निकला। विदेशी बैंक बहुत गोलमाल करते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है तो सबसे पहले विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हुआ तो जितने डिपाजिट्स हैं, मुझे डर है कि उनमें से बहुत से विदेशी बैंकों में चले जायेंगे और करोड़ों रुपये का नफा हमारे देश का इन विदेशी लोगों के पास चला जायेगा। इसको रोकने के लिए सदन को विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

SHRI NAMBIAR : Now the Swantantra Party is left alone.

SHRI S. K. TAPURIAH : We will rather be alone than with these anti-nationalists.

MR. DEPUTY-SPEAKR : The hon. Minister.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah) *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you an opportunity later on. We have taken more than one hour.

SHRI BENI SHANKER SHARMA : Sir, you had said in the beginning that those who moved amendments will be allowed to speak. My amendment is there but you have not called me whereas you have called others who have not given any amendment.

SHRI KRISANA KUMAR CHATTERJI : Sir, I will take only a minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister will reply from this side. If I give an opportunity to one Member from this side, I will have to give an opportunity to Members from this side also.

श्री वेणी शंकर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी एमेंडमेंट्स को पेश करते हुए मुझे केवल एक ही बात कहनी है । हमारी सरकार स्वदेशी की बात तो करती है, लेकिन वह काम विदेशी संस्थाओं को सरंक्षण देने का करती है । सरकार ने स्वदेशी बैंकों का तो राष्ट्रीयकरण किया; मगर विदेशी बेंकों को बिल्कुल छोड़ दिया है । यद्यपि बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक को पेश करने के पीछे राजनीतिक कारण हैं, परन्तु इस विधेयक में यह क्लाज रखने में और ऊंचे दरजे के राजनीतिक कारण मालूम होते हैं, जिन में विदेशों के एपीजमेंट की पालिसी का संकेत मिलता है । मुझे डर है कि इस प्रावधान के कारण स्वदेशी बैंकों में हमारे जितने डिपाजिट्स हैं, वे सब विदेशी बैंकों में चले जायेंगे और हमारी पहुंच से बाहर हो जायेंगे । इसलिए या तो विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, अथवा इन बैंकों को भारतीय लोगों के डिपाजिट्स लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाये, ताकि हमारे डिपाजिटर्ज का रुपया हमारे देशी बैंकों में ही रहे और देश की प्रगति के काम आ सके ।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am accepting Mr. P. C. Sethi's amendment No. 19, that is, for the word "the" "a" may be substituted and the reason is, under clause 7, we are providing for more than one tribunal, if necessary.

The purpose of all the other amendments and the speeches that we made was that not these 14 Banks only but all the Indian Banks and all the Foreign Banks transacting business here should also be nationalised. That is a point of view which probably reqnires further consideration. What I would submit is that before we proceed to nationalise a bank, a good deal of spade work has to be done......(*Interrnption*).

श्री रवि राय (पुरी) : पहले क्यों नहीं किया स्पेडवर्क ?

SHRI GOVINDA MENON : These is no use interrupting me. I was hearing silently to all that was being said. Please refer to clause 1(2) wherein it is stated that this law shall be deemed to have come into force on the 19th day of July, 1969. That is to say, the Ordinance was issued and these 14 Banks were taken over the Custodians appointed and preliminary steps taken—I may use that word if he does not like the use of the word "spade-work"—in order to see that these Banks come the public sector. With respect to that clause, the only amendment is from Mr. Abdul Ghani Dar who says that this law shall be deemed to have come into force on the 03st October,1969, that is to say, even the taking over will go (...*Interruption*) I am not raising any technical matter. These are matters which can be, by proper amendments, got over. The Government had in view that these bigger banks, as I said yesterday, with Rs, 50 crores or more by way of deposits should be nationalised and the steps taken and the arrangements made are for that purpose.

Now, the Prime Minister yesterday gave the reasons why these 14 Banks weae selected. I have nothing more to add to that.

श्री शिव चन्द्र झा : प्रधान मंत्री के तर्क में कोई दम नहीं था ।

SHRI GOVINDA MENON : It is a different matter, whether that was convincing or not.

With respect to foreign banks, I tnink, it is our desire also as a developing country to see that our banks the State Bank of India, all these nationalised banks and other banks, should have branches in other parts of the world so that international trade, so far as we are concerned, should be transacted and, therefore. some further thinking would be necessary on that matter apart from the reasons that the Prime Minister gave yesterday. In any event. speaking entirely from the legal point of view, the Introduction of the foreign banks will not be possible in the framework of the present legislation.

Some suggestions were made by friends like Shri Sreekantan Nair and Shri Kundu.

[Shri Govinda Menon]

If and when, the Government thinks of deciding to nationalise more banks, we can bring an amendment, we can have an ordinance and all these processes can be gone through.

श्री रवि राय : अभी कीजिए । अभी क्यों नहीं करते हैं ?

SHRI GOVINDA MENON : Now, the Government have taken a decision and the Goverment's decision is that today these 14 Banks should be nationalised. The question is put why not others also. The Government thought only about this matter and this is the Government's Bill...(*Interruption*)

श्री मधु लिमये : तो क्या हुआ ?

SHRI GOVINDA MENON : Why I said it is, it cannot come under the framework. Under article 117(1), no amendment which will involve expenditure on the part of the Government can even be moved. I do not want to raise that technical objection. I wanted to bear the members of the House because it will be of use to the Government in framing the policy for future.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have nothing to say about your pressing a particular amendment, but taking the particular amendments. I will put them separately, I will put amendments 4 and 5 : Thequestion is :

Page, 1,—

omit lines 10 and 11 (4)

Page 2,—

for lines 2 to 5, *substitute*—

"column 1 of the First Schedule ;" (5)

The Lok Sabha Divided :

Division No. 8] **[16.32 hrs.**

AYES

Abraham, Shri K. M.
Atam Das, Shri
Badrudduja, Shri
Banerjee, S. M.
Bhagaban Das, Shri
Bharti, Shri Maharaj Singh
Birua, Shri Kohli
Chakrapani, Shri C. K.
Chandra, Shekhar Singh, Shri
Dange, Shri S. K.
Dar, Shri Abdul Gandhi
Dwivedy, Shri Surendranath
Esthose, Shri P. P.
Fernandes, Shri George
Gopalan, Shri P.
Gupta, Shri Kanwar Lal
Haldar, Shri K.
Jai Singh, Shri
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri S. C.
Joshi, Shri S. M.
Kabir, Shri Humayum
Kalita, Shri Dhireswar
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kothari, Shri S. S.
Kripalani, Shri J. B.
Kundu, Shri S.
Kushwah, Shri Y. S.
Limaye, Shri Madhu
Madhukar, Shri K. M.
Mandal, Shri B. P.
Mangalathumadam, Shri
Meghachandra, Shri M.
Menon, Shri Vishwanatha
Molahu Prasad, Shri
Nair, Shri N. Sreekantan
Nair, Shri Vasudevan
Nambiar, Shri
Nihal Singh, Shri
Nihal Singh, Shri
Paswan, Shri Kedar
Patel, Shri J. H.
Patil, Shri N. R.
Ram Charan, Shri
Ray, Shri Rabi
Samanta, Shri S. C.
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Shri Deven
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Sheopujan
Sreedharan, Shri A.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Viswambharan, Shri P.
Viswanatham, Shri Tenneti
Yadav, Shri Jageshwar

NOES

Achal Singh, Shri
Agadi, Shri S. A.

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Aga, Shri Ahmad
Ahmed, Shri F.A.
Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Ankineedu, Shri
Arumugam, Shri R. S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Basu, Dr. Maitreyee
Basumatari, Shri
Bhagavati, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Buta Singh, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chatterjee, Shri Krishna Kumar
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri D.R.
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmiki
Coudhury, Shri J. K.
Dalbir Singh, Shri
Dandeker, Shri N.
Das, Shri N. T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Deb, Shri D. N.
Devinder Singh, Shri
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ering, Shri D.
Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C. D.
Ghosh, Shri Bimalkanti
Ghosh, Shri P. K.
Govind Das, Dr.
Gowd, Shri Gadilingana
*Gowda, Shri M. H.
Gowder, Shri Nanja
Gupta, Shri Lakhan Lal
Gupta, Shri Ram Kishan
Hanumanthaiya, Shri
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J. N.
Hem Raj, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V.N.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Jamna Lal, Shri
Kahandole, Shri Z. M.
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Karan Singh, Dr.
Katham, Shri B. N.
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri M.A.
Kinder Lal, Shri
Kripalani, Shrimati Sucheta
Krishna, Shri M. R.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Lobo Prabhu, Shri
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahida, Shri Narendra Singh
Majhi, Shri Mahendra
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Marandi, Shri
Masani, Shri M. R.
Master, Shri Bhola Nath
Masuriya Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Mehta, Shri P. M.
Melkote, Dr.
Menon, Shri Govinda
Minimata, Agam Dass Guru Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mody, Shri Piloo
Mohammad Imam, Shri J.
Mohsin, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Mulla, Shri A. N.
Murti, Shri M. S.
Naghnoor, Shri M. N,
Naidu, Shri Chengalraya
Naik, Shri R. V.
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Pandey, Shri K. N.
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri

*wrongly voted for NOES

Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manubhai
Patel, Shri Anantrao
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. D.
Patodia, Shri D. N.
Poonacha, Shri C. M.
Pradhani, Shri K.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Raghu Ramaiah, Shri
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Dhani Das, Shri
Ram Sewak, Shri Choudhary
Ram Swarup, Shri
Ramamurti, Shri P.
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Randhir Singh, Suri
Ranga, Shri
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri J. Ramapathi
Rao, Shri Thirumala
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri Ganga
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Saleem, Shri M. Yunus
Sambasivam, Shri
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prssad, Dr.
Sarma, Shri A. T.
Satya Narain Singh, Shri
Savitri Shyam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shah, Shri Shantilal
Shah, Shri Virendrakumar
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Madhoram
Sharma, Shri Naval Kishore
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shivappa, Shri N.
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Snatak, Shri Nar Deo
Somani, Shri N. K.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Surendra Pal Singh, Shri
Sursingh, Shri
Swaran Singh, Shri
Tapuriah, Shri S. K.
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Ulaka, Shri Ramachandra
Veerappa, Shri Ramachandra
Venkatasubbaiah, Shri P.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the Division is :

Ayes : 59; Noes : 198.

The motion was negating

MR. DEPUTY-SPEAKER : Which are the other amendments to be put separately? I will take one by one the amendments which hon. members want to be put to vote separately.

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Dr. Surya Prakash Puri, Shri M. H. Gowda, Shri Janshwar Misra, and Shri Swami Brahmanandji.

NOES : Sarvashri M. Sudarsunam, R. D. Reddy, D. D. Jena, S. P. Ramamoorthy, and Shrimati Sudha V. Reddy.

I shall now put amendments Nos. 13 and 14 to the vote of the House.

Amendments No. 13 and 14 were put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 154 to the vote of the House.

Amendment No. 154 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the amendment No. 162 to the vote of the House.

Amendment No. 162 was put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 169 to the vote of the House.

Amendment No. 169 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 204 to the vote of the House.

Amendment No. 204 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 318 to the vote of the House.

Amendment No. 318 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 381 to the vote of the House.

Amendment No. 381 was put and Negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendments Nos. 106 and 107 to the vote of the House.

Amendments Nos. 106 & 107 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Excepting the government amendments, I shall now put all the rest to vote.

Amendments Nos. 14, 44, 46, 47, 62, 63, 175, 197, 198, 205, 281, 317, 335 to 337, 371, 380 and 382 *were put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

Page 2, line 13,—*for* "the", *subistitute* "a", (119).

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 2, as amended was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is an amendment for a new clause —2A—by Shri Yashpal Singh. He is absent.

Clause 3 (*Establishment of corresponding new banks and buisness there of*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : If I permit overlapping, there will be no end to it. Wording and substance may not be taken separately. If an amendment is different from another but the substance is the same and we devote time in speeches to both, we lose a lot of time. So far as observations are concerned, I will just allow a minute and half to each member. Otherwise, it is impossible. If we are not able to cover the whole thing within time, I will have to guillotine the rest of the clauses.

The following are the amendments that are being moved to clause 3 : 64, 92, 108, 156, 157, 176, 177, 209, 219, 282, 303, 319 and 330.

SHRI ABDUL GHANI DAR : I beg to move :

Page 2, lines 34 to 36,

Omit "and shall have power to acquire and hold property, whether movable or immovable, for the purposes of its business and to dispose of the same" (64).

SHRI HUMAYUN KABIR (Basirhat) : I beg to move.

Page 2,—

after lines 27, *insert*—

"Provded that within sixty days after

[Shri Humayun Kabir]

the capital has so vested, the central Government shall retain thirty per cent. of the shares and offer the remaining seventy per cent. to the public at par in the following manner :

(a) Shareholders and employees of the existing bank shall have first preference in the allotment of such shares :
Provided that no individual whether a person or a body corporate shall be allotted or permitted to hold jointly or severally more than ten per cent. of such shares.

(b) In case the shares of the corresponding new bank are allotted to a shareholder of the existing bank, such shareholder shall not be entitled to any compensation for the number of shares allotted to him." (92)

SHRI S. M. BANERJEE : I beg to move :

Page 2,—

omit linee 28 to 30 (156)

Page 2,—

after line 42, *insert*,—

"(7) The new banks togethersh all be a body corporate with perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued in its name."(157).

SHRI MADHU LIMAYA : I beg to move :

Page 2,—

After line 36, *insert*—

"Provided that no advances either secured or unsecured shall be granted to political organisations and individuals far political purposes. (Illustration : Giving of an advance to AICC shall come within this provision)." (176)

Page 2,—

after line 42, *insert*—

"(7) The Central Government may take over any other bank whose name does not appear in the First Schedule now at any time by issuing a notification in the Gazette.". (177)

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : I beg to move.

Page 2,—

after line 20, *insert*—

"Provided that the Central Government shall not effect amalgamation or absorption any of new banks without the express sanction of Parliament ; and at no time shall there be less than five State-owned new banks, reconstituted as necessary, functioning in the country." (209)

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I beg to move.

Page 2, line 26,—

for "entire capital" *substitute*—

"fifty-one per cent. of the Capital" (219)

SHRI N. K SOMANI : I beg to move.

Page 2,—

for lines 26 and 27, *substitute*—

"(3) The capital of each corresponding new bank upto 51 per cent. Shall stand vested in and allotted to the Central Government." (303)

SHRI NAMBIAR : I beg to move.

Page 2, line 36,—

add at the end—

"and to amalgamate with other banks when found necessary." (319)

SHRI BENI SHANKER SHARMA : I beg to move.

Page 2,—

for clause 3, *substitute*—

"(3) On the commencement of this Act, or as soon as the arrangements are complete all the banks as specified in the First Schedule shall be amalgamated with the State Bank of India." (330)

SHRI CHINTA MANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : I beg to move.

Page 2, line 34.—

after "Act" *insert*—

"subject to the directtons of the Central Government regarding credit control and investment regulations according to plan priorities." (108)

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar) : I beg to move.

Page 2,—

after line 36, *insert*—

"(5A) All deposits in the corresponding new banks shall be guaranteed as regards their repayment in full by the Central Goverument." (282)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Just listen. We are on clause 3. If one point is made here and the points on an amendment are repeated, I will not permit the Member to make his submissions. For one group, I will allow one Member. If the amendment is different, then a second person will be permitted to speak. That is the procedure that I am going to follow. Otherwise, there is no end to it. Shri Humayun Kabir.

SHRI HUMAYUN KABIR : Mr. Deputy-Speaker, Sir I had asked for time to speak during the general discussion, and you were aware of it, but in spite of your intentions you were not able to give me time. I have nevertheless to make one or two remarks about the hsatily drafted nature of the Bill. On the 19th, the Ordinance was issued and on the 23rd July, this Bill was brought up. Within these four days, the Government came with 12 amendments, some of them of a fairly major nature. Between the 23rd and today, as my hon. friend Shri Menon himself admitted, due to the excellent suggestions of my young friend, Shri Sethi, who is a very hardworking young man, many more amendmens have been brought. in. Actually, the new amendments brought by the Governments are perhaps longer and more elaborate and more detailed than even the provisions in the original Bill. All this suggests that this is a Bill which should have been sent to the Select Committee. I think we are not doing justice to this House and we are not doing justice to the importance of the Bill. We are not doing justice even to the Government since the Government will throw itself open to accusations of gerrymandering by bringing this Bill in a hastly manner.

16.41 hrs.

[SHRI P. K. VASUDEVAN *in the Chair*].

However, I propose now to confine my remarks to the amendment which I have moved. It has been established as a result of the voting that there is overwhelming support for result of the voting that there is overwhelming support for nationalisation of banks. But there are very great differences about what nationalisation means. I think the House is aware that very often what passes as nationalisation is merely the substitution by one set of irresponsible persons. The major criticism against private ownership of banks and similar instruments of production has been that they can can wield the resources of the community according to their own wishes.

What is happening by this Bill ? In the place of certain private individuals, we are appointing certain officials. We are not having nationalisation. We are having what may be called the State capitalism or what may be called a glorification of the bureaucracy. I have nothing against our bureaucracy. I know some of our officers are among the ablest in the world, and I have also the greatest respect for the integrity of many of them and I have heard them very highly praised. Nevertheless, it has to be admitted that the whole executive approach, the bureaucratic approach is something which is entirely different from the approach which you need in trade and industry, which you need in banking and similar financial and monetary transactions.

What we are doing now is to transfer the control of the assets of the nation from the hands of a number of private individuals to one single central source.

[Shri Humayun Kabir]

The concentration of political power in the hands or any single individual or group is dangerous enough, but when you have a concentration of economic power in addition to the concentration of political power, you create a situation where the fact of the ordinary man is in jeopardly. This is what we are facing today.

I am for social control ; I am for nationalisation ; but nationalisation in the real sense. That is why I have suggested in this amendment a new conception of nationalisation. We want that the policy should be controlled by the Government which is after all the spokesman of the country so long as it enjoys the confidence of the people. I was astonished at one stray remark of my hon. friend Shri Govinda Menon in his reply to the debate on clause 2. He said, that this is a Government Bill and therefore we must all accept what ever the Government decides. Well, a Bill may be introduced by the Government, but once the Bill is before the House, it is the property of the House. I think any Governments with any sense would recognise that the collective wisdom of the House as a whole should be brought to bear upon the provisions of the Bill. If the Government take up the attitude that because we have said 'X' on a particular date, we cannot 'say' on a different date, that is an entirely wrong approach.

This remark itself is evidence of the way in which Government's mind is moving. Therefore, if we allow this concentration of power in the hands of a coterie, in the hands of a political group—and that is after all what it boils down to—it will not be proper. We have a party Government and so long as we have a party government—whether it is the Congress party today or some other party—it will always be a party government in a parliamentary Democracy. Sir, this kind of concentration of power in the hands of a single group will be dangerous. That is why I have suggested that nationalisation should be given a new conception.

MR. CHAIRMAN : The hon, Member should try to conclude now.

SHRI HUMAYUN KABIR : (Basirhat) Sir, as I said in the very beginning, this amendment goes to the very heart of the matter. I hope you will admit that I am not repeating my arguments. I am making certain points which have not been brought out by anybody before. It is a new attitude towards nationalisation, a new method by which we can have the gdvantages of private ownership as well as public control. If you do not allow me to express my point of view I will, of course, sit down, but I will say in that case the farce of discussing this Bill in this House should not be continued any longer, all of us might depart and the Government might with empty benches here pass anything they like,

Sir, I submit that the amendment I have moved goes to the very heart of the matter. We want that the ultimate control should be in the public sector, should be in the hands of the Government, but this can be done according to our laws if 25 per cent or more shares are under the direct control of Government. If at the same time, the remaining shares are given to to the public so that the public have a share and intere st in the affairs of banking organisation, it will make for efficiency. We have seen that heritation wherever there is a public sector—I do not say delays and private sector is always more efficient, private sector is sometimes inefficient also. If we can have a judicious mixture of both public and private sectors we can have better administration and control. That would not be the case if we have monopoly of any type, whether of State or private individual.

One remark of the Prime Minister which I welcomed during her speech yesterday was when she said she is against monopoly. She said she does not propose that these different banks should be amalgamated and that it would have a monolithic structure. I would like to make it very clear I am a socialist but I do not believe in monopoly whether it is monopoly by the State or by any individual, and if there is monopoly by the State...- -I know my friend Shri Dange is laughing because he is still thinking in terms of theories which were probably prevalent and curent fifty years ago (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN Order, order. There is no time for Interrupions.

SHRI HUMAYUN KABIR: I was saying that my amendment provides the advantages of both if subject to the condition that nobody except the Government can hold more them ten percent of the shares, a majority of the shares are held by private individuals, it will make for efficiency and better administration. Such shareholders will certainly want adequate returns from the bank operators. They will also have a certain reproducrion on the board of directors. If the boards of directors are so constituted that the share distribution is also reflected in the composition of the directors we shall have greater efficiency.

What happens today is that a few private individuals invest 1½ per cent or 2 or 3 per cent and they have the control over the entire asets of the bank. There is only one check. If they mismanage, if they have a loss they also suffer that loss. If you have bureaucratisation, you have the evils of capitalism without any of the advantages of socialtsation. Under bureaucracy, whether a concern is well maraged or ill managed, whether there are profits or losses, in either case the bureaucrats will go on drawing their salaries. They have no stake in the matter. If, on the otherhand, we adopt the scheme I have suggested, in which a major part of the shares really belongs to the community and the community therefore has a voice in the administration of the affairs but the general control, the overall control and direction of policy is in the hands of the Government, we get all the benefits of nationalisation, all the advantages of social control and at the same time we avoid the pitfalls of the mistake which follows from the over-concentration of power in the hands of a few. With these words, I commed my amendment for the acceptance of the House.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: (Bhubaneswar) Mr Chairman, the nationalisation of banks is a welcome measure. It is in keeping with the prevailing mood of the nation which in for rapid economic changes in the society. Therefore, the realities of life and pragmatism demand this measure and it is better that those who are opposing it should try to adjust themselves to it.

Here I want to say that nationalisation by itself is not an end. It is only a means to an end. The major banks have been nationalised to give a new direction so our national policy and objective. Clause 3 of the Bill says that the business of the new natienalised banking companies will continue as at present, under section 6 (1) of the Banking Companies Regulation Act, 1949. I think it needs to be changed. After the nationalisation of banks, we have to nationalised the distribution of resources between the borrowers, between the big medium and small producers. There should be selective investment. There has been so much of changes after we passed the Banking Companies Regulation Act in 1949. Therefore, if we allow the banks to continue business in the same old way then there is no improvement in the situation after nationalisation.

As the Prime Minister has stated government want to pursue a new and vigorous phase of economic development in this country. Therefor, government should try to see that speculative investment which banks pursued when they were private commercial bauks are not allowed to be continued when the banks are nationalised. This needs immediate attention. Therefore, I have suggested the addition of the words "subject to the requirements of the policy objectives".

Here I would like to draw the attention of the House to the report of the Licening Inquiry Committee headed by Shri Dutt. Even thouge we have nationalised the State Bank of India and Life Insurance Corporation, due to luck of any clear priorities, and as the objectives were not clearly laid down by the Planning Commission and the Ministry of Finance, we have come to a sitution where 87 per cent of the investment of the State Bank of India has gone to 20 big monopoly houses and 97 per cent of the LIC investment has gone to such big business houses, even though that was not the intention of the government or the aim of the government. In view of the changed conditions which the Law Minister announced in the House, government must have unrestricted power to give directions to the nationalised banks in puresuance of the declared objective of the government,

After the nationalisation of banks a new problem has arisen to which I wolud

[Shri Chintamani Panigarhi]

like to draw the attention of the House, Nationalisation meant the greatest good to the greatest number. In this hon. House so long hon. Members belonged only to two sexes ; they were either men or women. After nationalisation a change of sex has come in, which cannot be ignored. Now there are certain members who are feeling thank they are becoming eunuchs. The political parties have to adjust themselves to these eunuchs after nationalisation.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, I would like to begin by equating myself to Cassandra. rather the true prophetess, who was referred to by the Prime Minister. I had the good fourtune or bad fortune of pointing out the constitutional defects of the Gold Control Order and everyone of my points have been accepted by the Supreme Court.

I would like to say here that we, as an Opposition party who respect the dignity of this House, should not pass a Bill which would be struck down mercilessly by the Supreme Court and you, who are so attached to this Bill which is before you, should not pass such a Bill.

I have all respect for the Minister of Law and I would like him to refer to a single point, that this Bill must have a public purpose. Unless it has a public purpose, article 31 is not effective and you cannot acquire transfer in property. What is the public purpose served by this Bill ?

We have an example of the State Bank which commands 33 per cent of the banking structure. Having commanded that structure. one must see how take loans from the bank. The figures are there. Against 33 per cent which is its financial strength, its deposits and up only to 21·3 per cent. In respect of it advances or credit, it is only 21 per cent. It has not attracted private deposits to any extent. A good part of its deposits are Government deposits and the public deposits are largely in the scheduled banks. I do not want to be facetious but a time will come when it will be as difficult to make a deposit in the bank as to pay a challan in to the Treasury. That is the position about deposits.

Deposits come because there is security. Where is the security for Government loans ? You have co-operatives where the overdues add up to 37 per cent. You have the Government loans or taccavi which adds up in some States even to 70 per cent which is not rapid. If anybody is going to put his money in a bank, advances from it will be similar proportions as of overdues and bad debts. This is the position we are facing. If it is 21 per cent now, as soon as you add this 55 per cent more of the 15 nationalised banks you will probably find that deposits shrink to nothing.

The Prime Minister was concerned about it. All of us are concerned about it, because if deposits do not go into the bank, they will go into other undesirable forms of investmant. They will go into usury, financial institutions or undesirable consumption expenditure. If you are, therefore, thinking of a public purpose being served, it is not being served when you reduce other banks to the level of the State Bank.

In respect of advances for social purposes, namely, for agriculture, small-scale industries, employment, exports, I asked a question in this House and I received the reply that the State Bank has the lowest proportion in all these advances. Instead of taking advantage of these private banks which had a high ptoportion, we are now going to condemn them to level of State Bank which fails to give money for public purposes. I may point out that in my own home town out of 61 tile factories, which are eligible for loans as small-scale industry at 7 per cents, only two have approached the State Bank for these loans and the rest are content to pay even up to 13 per cent to private banks. This is the difference between the State Bank and a private bank, namely, that a private bank's loan at 13 per cent is better than a State Bank loan at 7½ per cent. So, public purpose is not served by nationalisation.

What purpose then is served ? My friends are deluded : they are not seeing what is the meaning of this Bill. The meaning of this Bill is that Government is going to take charge of Rs. 4,000 crores and the power that it gives over the industry and trade to wipe them out...(*interruption*)

SHRI NAMBIAR : It is the people's money.

SHRI LOBO PRABHU : They are not only not going to wipe out the Swntara Party—the Swatantra Party may survive because of its merit—but they are going to wipe out all that rubbish on the other side which dedends on nothing.

17 hrs.

I would like to say this is political game ; this is not going to serve the comman man......

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may try to conclude now.

SHRI LOBO PRABHU : We are fortunate to have you in the Chair.

MR. CHAIRMAN : The Deputy-Speaker has said that two or three minutes each may be given.

SHRI LOBO PRABHU : Please give me only three minutes.

MR. CHAIRMAN : I have already given you five minutes.

SHRI LOBO PRABHU : Only two or three minutes more.

MR. CHAIRMAN : You have not yet come to your amendment.

SHRI LOBO PRABHU : That is why I want two or three minutes more. I am coming to my amendment.

Are you going to serve the common man by arresting to change in the economy that was taking place ? Are you going to serve the common man by paralysing credit which is the life blood of the economy ? You are not. You are going to introduce conditions where unemployment will increases ; you are going to introduce condiditions where you will be faced with so much distress that in spite of all the money, all the power, you can get from this Bill, you will also be wiped out. You will have a dictatorship ; you will have a revolution. (*Interruption*) I am now coming to my amendment. You have a mixed economy and in a mixed economy, both the private sector and public sector co-exist. As my hon. friend, Shri Humayun Kabir, suggested 25 per per cent, I go a little further and I would ask the Government to have 51 per cent of the capital and leave 49 per cent to private sector. You will have all the power that you require to control the private sector; It will also give a sense of confidence to the people that you are not becoming communist and that you are not going their way. Therefore, I would like to say it is a very simple amendment. Please you meet my objection of "public purp se" and if you cannot meet if fully, at least, you may accept my ammendment which reduces the gravity of the transgress on the Constitution.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsam) : Sir,I should like to emphasise that the Bill envisages that a scheme will be brought subsequently. In my opinion, the scheme should have formed part of the Bill itself. It amounts to excessive delegation of authority. On these grounds the Supreme Court would strike down this place of legislation, as has already happened in the case of a part of the Gold Control Act. I am sounding a note of warning to the Government on this point. The scheme forms such an important part of the subsequent set up, the post nationalisation set-up, that it must be included in the Bill itself. It is an exeescessive delegation of authority.

Secondly, I would submit that all these 14 Banks should be kept as individual units. Even if there is some amalgation, there should be a minimum of at least five units functioning besides the State Bank of India. This is absolutely necessary so that these units may compete amongst each other and we do not have inefficiency as we find in the case of a huge organisation like LIC. Actually, the then Finance Minister and the Deputy Prime Minister, Shri Morarji Desai, said that they were even considering that the LIC should be split up into two or three zonal corporations. I would submit that a minimum of five units should be maintained.

Another point that I should like to emhasize is that the process of bureaucratisation, which will inevitably follow nationalisation, is going to do considerable harm to the economy and, particulary, to the service that is given to the depositors. What is necessary is that the management should be professionalised. Actual professional bankers should be put incharge of them and there

[Shri S. S. Kothari]

should be minimum of interference by bureaucrats sitting in the North Block or the South Block of the Secretariat. That is very necessary.

Besides that, it is important that if any fundamental changes are made, they should be made with the consent of Parliament. The Government does not have any authority to bring in a measure which would change the entire structure in some form or the other and do it without the consent of the Parliament.

There have been talks that nationalisation is going to add to the resources of the Fourth Plan which is going to be revised. I do not understand how resources would be released for the fourth plan. An analysis of the assets and liabilitities show that cash is 8.7% of deposits ; advaces amount to 68.6% ; investments amount to 28.5%. Rs. 27 crores are invested in industrial securities. Out of 2742 crores I do not see how many can be released for the plan. They may liquidate part of the individual investment. The important point is if the money of these banks is utilised for increasing the loans to public undertakings which do not give any return the consequence would be that there would be no profits and the rate of interest they pay to the depositors would be reduced and what they charge the borrowers would be increased. That will have a deleterious effect on industrial development. Therefore, I submit that there is no money except the Rs. 27 creres which is about 1%. There would be no release of funds for plan purposes. This is what I want to emphasize.

श्री अबदुल गनी डार : कल प्रधान मंत्री जी ने फरमाया था कि हम कोई मौनोपोली बनाने नहीं जा रहे हैं या पार्टी पालिटिक्स के लिए खर्च नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं ला मिनिस्टर को सुनता हूं तो मुझे याद आता है "मन चे मीं सरायम व तम्बूराए मन चे मी सरायत"। मैं क्या कहता हूं और मेरा ला मिनिस्टर क्या कहता है। आप पूरी ताकत अपने हाथ में बैंकडोर से लेना चाहते हैं। कबिर साहब और कुछ प्रोग्रेसिव लोग जो हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ चाहा है कि मिक्स्ड इकोनोमी हो जाए। यह हो सकता है कि वह कहते हों पच्चीस परसेंट और लोबो प्रभु साहब कहते हों 51 परसेंट या कोई फिर से मोटे आदमी न आ जाए। मैं चाहता हूं कि सब किसानों को दे दो। वे अपना रुपया जमा करायें। इस में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जो ये पूरे अखत्यारात ले रहे हैं, उस पर कोई शर्त लगायी जानी चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं, प्रधान मंत्री कहती हैं कि हम अन्दरूनी मामलात में दखल नहीं देंगे, सिर्फ पालिसी बनायेंगे, हम इंस्ट्रकशंज़ देंगे लेकिन दूसरी तरफ पूरी ताकत आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ जैसे पहले हुआ है पब्लिक सैक्टर में कि उनको यू० पी० एस० सी० के परव्यू से निकाल लिया गया और जितने नालायक लोग थे उनको वहां भेज दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना का नुक्सान हुआ, तब क्या होगा ? प्रधान मंत्री ने फरमाया तो है कि हम मौनोपोली बनाना नहीं चाहते हैं लेकिन इस बिल में वैसी कोई बात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि हारे हुए जितने लोग बाकी हैं उनको कहीं न कहीं आप लेना नहीं चाहते हैं। मुझे डर है कि विक्टमाइजेशन भी होगा। मैं चाहता हूं कि बददयानतदार जो लोग हैं उन पर तो काबू पाया जाए लेकिन दयानदार जो हैं जिन्होंने सर्विस देश की की है, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिये। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्राइवेट बैंकों में ऐसे बैंक हैं चाहे बैंक आफ इण्डिया हो या बड़ौदा बैंक हो या कोई और हो जिन्होंने दयानतदारी के साथ देश की खिदमत की है, सनतों की खिदमत की है। इसलिए सब को एक लाठी से हांकना अक्लमन्दी की बात नहीं है।

इस वास्ते मैं कहूंगा कि जो इन्होंने कहा है ला मिनिस्टर उस पर गौर फरमायें। बेशक 49 परसेंट कम्युनिस्टों को दे दिया जाय या एस एस पी को दे दिया जाए, मुझे कोई एत-

राज नहीं है । लेकिन मैं चाहता हूं कि या यह न कहो कि मौनोपोली आप नहीं चाहते हैं, पार्टी पालिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, जैसे अभी देश को बरबाद कर रहे हैं उस तरह से बरबाद करना नहीं चाहते हैं, या फिर इस बात को मानो कि ऐसा होना चाहिये जिससे देश का फायदा हो ।

[شری عبدالغنی ڈار : کل پردھان منتری جی نے فرمایا تھا کہ ہم کوئی مونوپولی بنانے نہیں جا رہے ہیں یا پارٹی پالٹیکس کے لئے خرچ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب میں لا منسٹر کو سنتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے۔ من چے میں سرایم وتمبو رائے من چے بی حضرات میں کیا کہتا ہوں اور میرا لا منسٹر کیا کہتا ہے۔ آپ پوری طاقت اپنے ہاتھ میں بیک ڈور سے لینا چاہتے ہیں۔ کبیر صاحب اور کچھ پروگریسو لوگ جو ہیں انھوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چاہا ہے کہ اکونوس ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہو ان کچھ پرسنٹ اور لوہو پر کھو صاحب کہتے ہیں ۵۱ پرسنٹ یا کوئی پھر سے موٹے آدمی نہ آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کسانوں کو دے دو۔ وہ یا اپنا روپیہ جمع کرائیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو یہ پورے اختیارات لئے رہے ہیں اس پر کوئی شرط لگائی جانی چاہئے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں پردھان منتری کہتی ہیں کہ ہم اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ صرف پالیسی بنائیں گے۔ ہم انسٹرکشنز دیں گے لیکن وہ دوسری طرف پوری طاقت آپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے ایسا ہوا جیسے پہلے ہوا ہے پبلک سیکٹر میں ان کو یو۔پی۔ ایس۔ سی کے پرویو سے نکال لیا گیا۔ اور جتنے نالائق لوگ تھے ان کو وہاں بھیج دیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اربوں روپیہ سالانہ کا نقصان ہوا تب کیا ہوگا۔ پردھان منتری ہم نے فرمایا تو ہے کہ مونوپولی بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اس بل میں ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ہوتے جو لوگ باقی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ لینا نہیں چاہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ دکٹیٹرشپ بھی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ بد دیانتدار جو لوگ ہیں ان پر قابو پایا جائے لیکن دیانتدار جو ہیں جنہوں نے سروس دیش کی کی ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہئے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ بینکوں میں ایسے بینک ہیں چاہے بینک آف انڈیا ہو یا پنجاب سوده بینک ہو یا کوئی اور ہو جنہوں نے دیانتداری کے ساتھ دیش کی خدمت کی ہے۔ صنعتوں کی خدمت کی ہے اس لئے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا عقلمندی کی بات نہیں ہے۔

اس واسطے میں کہوں گا کہ جو انھوں نے کہا ہے لا منسٹر اس پر غور فرمائیں۔ بے شک ۴۹ پرسنٹ کمیونسٹوں کو دے دیا جائے یا ایس۔ ایس۔ پی کو دے دیا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ مونوپولی آپ نہیں چاہتے ہیں پارٹی پالیٹکس کے لئے استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی دیش کو برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے برباد کرنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر اس بات کو مانو کہ ایسا ہونا چاہئے۔ جس سے دیش کا فائدہ ہو۔]

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन 176 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि श्री गोविन्द मेनन कम से कम इस संशोधन को मान लेंगे । मेरा संशोधन यह है :

after line 36, *insert*—

"Provided that no advances either secured or unsecured shall be granted to political organisations and individuals for political purposes

[श्री मधु लिमये]

(Illustration: Giving of an advance to AICC shall come within this provision)."

श्री गोविन्द मेनन ने अभी कहा कि यह सरकारी बिल है. इस बारे में हमारा दिमाग बना हुआ है, इसलिए हम इस में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे । लेकिन जो परिवर्तन मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह बुनियादी नहीं है, बल्कि इस बिल के उद्देश्यों से इसका बराबर सम्बन्ध है । प्रारम्भ में ही इस बिल में कहा गया है कि यह बिल किस लिए है ।

"...in order to serve better the needs of development of the economy in conformity with national-policy and objectives and for matters connected therewith or incidental thereto."

इसी तरह स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज़ में भी कहा गया है :

"The banking system touches the lives of millions and has to be inspired by a larger social purpose and has to subserve national priorities and objectives, such as rapid growth in agriculture, small industries and exports, raising of employment levels, encouragement of new enterpreneurs and the development of backward areas."

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ए० आई० सी० सी० या इस प्रकार के अन्य संगठन खेती, एग्रीकल्चर में आते हैं, स्माल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं या एक्सपोर्ट्स में आते हैं; अगर रेज़िंग आफ एम्पलायमेंट लेबेल का यह मतलब है कि ए०आई०सी०सी० में ज्यादा लोग रखे जायें तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर यह बात नहीं है, तो मंत्री महोदय को इस संशोधन को स्वीकार करने में क्या तकलीफ है ? मैं इस से भी आगे जा कर कहता हूं कि अगर मन्त्री महोदय यह आश्वासन दें कि वह जो योजना या नियम बनायेंगे, उनमें वह इस व्यवस्था को शामिल करने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपने इस संशोधन को वापस लेने के लिए तैयार हूं ।

जैसा कि सब जानते हैं, हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के हक में हैं और हम तो चाहते थे कि बाकी बैंकों को भी ले लिया जाये, लेकिन सरकार जिन चौदह बैंकों को ले रही है. उन का काम सुचारु रूप से और राष्ट्रीय हित में चले, इसकी हम सरकार से गारण्टी चाहते हैं, वर्ना हमारे मनों में सन्देह उत्पन्न हो रहा है कि 1972 के चुनावों में इन बैंकों के द्वारा ए० आई० सी० सी० को कर्जा दिया जायेगा । माननीय सदस्य, श्री डार, अभी शान्ति प्रसाद जैन की बहुत चिन्ता कर रहे थे । इस समय मैं पंजाब नेशनल बैंक का नाम बार बार ले रहा हूँ, जो कि शान्ति प्रसाद जैन की है । शान्ति प्रसाद जैन के पंजाब नेशनल बैंक और बिड़ला के युनाईटिड कामर्शल बैंक, इन दोनों ने मिल कर पिछले मध्यावधि चुनावों के अवसर पर ए० आई० सी० सी० को पच्चीस लाख रुपये का एडवांस दिया । क्या यह समाजहित में नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है ?

मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं । मुझे बिहार के भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि 1951 के बाद प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू, और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, के बिहार में जितने दौरे हुए हैं, उनका पैसा सदाकत आश्रम को सरकारी कर्ज के नाम से दिखाया गया है और सदाकत आश्रम को सरकार ने जो कर्जा दिया है वह अभी तक वापस नहीं लिया गया है। मैं यह भी जानकारी चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उस एडवांस को लौटा दिया है और मैं मंत्री महोदय से भविष्य के लिए साफ आश्वासन चाहता हूँ, वर्ना मैं उन्हें यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर देश में बड़ा विद्रोह होगा और खून की नदियांभी बहेंगी ।

अगर इस पैसे का इस्तेमाल जनता के खिलाफ किया गया तो ।

अन्त में एक ही बात मैं कहना चाहता हूं । दूसरा एक जो संशोधन है 36 (ए)(डी) के बारे में, 36 (ए)(डी) को हटाने वाला संशोधन है नम्बर 190 । मैं केवल उसकी ताईद कर रहा हूं । राममूर्ति जी का संशोधन है । मैं केवल उसका समर्थन कर रहा हूँ कि देश हित में अगर यह विधेयक है तो मजदूरों पर, कर्मचारियों पर और ट्रेड यूनियन्स पर जो नियंत्रण लगा कर रखे हैं उनको हटाया जाय । उनको हटाने की मांग का मैं समर्थन करता हूँ ।

SHRI S. M. BANERJEE : My amendment is simple ; it is to insert a sub-clause that the new banks together shall be a bodycorporate with perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued in its name. The earlier amendment was to omit lines 28 to 30. While moving this amendment, I support the amendment of Shri Madhu Limaye. The hon. Law Minister wants nationalisation. He should see that there is no corruption. At present because they are run in the private sector there is mismanagement. I am thefore sure that the amendment would be accepted. I want to ask whether Rs. 25 lakhs had been paid to the AICC.

SHRI NAMBIAR : My amendment is simple. It wants to add at the end of the clause "and to amalagamate with other banks when found necessary." They are now taking over fourteen banks and the whole country applauds it. Now these fourteen banks are going to operate simultaneously but separately. We have the State Bank also operating in those places. What is going to happen is that these fifteen banks will operate in every town and city and each bank will have its branches. Therefore, it will look as though 75 or 80 separate banks are operating in a small city like Madras or Trichy. When we proceed further, there will be need for amalgamation. Amalgamation does not mean retrenchment but improvement in quality, work and service. I do not want amalgamation here and now.

SARI GOVINDA MENON : The Government are moving an amendment in order to effect the objective which Mr. Nambiar has in view. That is amendment No. 130. We are taking power to amalgamate if necessary.

SHRI NAMBIAR : Thank you. One word of caution. When amalgamation takes place it should not reduce the employment potential of the personnel...(*Interruption*). Further, there is another point which I wish to make. That is the question of bureaucrats ; those persons will continue, and their manipulations will continue. Therefore, when the next clause is taken up, I shall be moving another amendment saying that those officers, controllers, or what you call Chairman or the managing directos, all these bureaucrats should be removed completely. That should be done. We want a new set up so that those men who were misbehaving and who ruined and did all sorts of malpractices utilising the common man's money which is entrusted to them, should not be there ; such things should not be allowed to be repeated in the name of good administration. If the Government really repeat such things, as they did in the case of the LIC, the whole scheme will be prejudiced and the whole thing will become futile, and then it will be said, "See, the nationolised banks have gone to dogs."

Learn the lesson from the LIC, and learn the lesson from the public undertakings, and learn the lesson precisely and strongly, so that the old bureaucrats will not be allowed to control the banking institutions. Give them good pension, provident fund good facilities, and then ask them to quit, and quit for the country's good.

MR. CHAIRMAN : I am afraid Mr. Somani's amendment is the same as that of Mr. Lobo Prabhu. He might have different things to say but the amendment is just the same. Mr. Patodia.

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : My amendment No. 282 seeks to introduce a new sub-clause to clause 3. It reads:

> "All depositors in the corresponding new banks shall be guaranteed as regards their repayment in full by the Central Government."

We have heard various Government spokesmen saying that nothing should be said either in the House or outside the House which may shake the confidence of the depositors. But nevertheless, whatever that has been said by the Government spokesmen, the manner in which it has been brought about has clearly shaken the confidence of thedepositors. There is no doubt about it.

Government has justified it by saying that if banks are once nationalised, the depositors are safe as long as the Government is there, as long as the Government is solvent. If that be the ground, if that be the justification of the Government, and if they stand by that, here is an occasion, here will be a test of their *bona fides* to find out if they are prepared to accept this amendment which is a very simple one, saying that Government will guarantee repayment of loans up to 100 per cent.

There are two positive aspects to it. If there is any scare—it is there—and if they accept this amendment with regard to the existing depositors, the depositors will have the fullest possible confidence and they will not have any hesitation and there will be no withdrawal and no run. Apart from that, the second and the more important point is that if they accept this amendment, they would be in a position to attract more deposit in future. Therefore, I believe that the Government will be good enough to accept the amendment, because to refuse it will be dangerous. Having moved this amendment, they should appreciate that any refusal will mean that they are not prepared to ensure full repayment to the depositors.

Before I conclude, let me say a few words with regard to amendment No. 176 which has been moved by my friend Shri Madhu Limaye. This is an amendment over which I feel that no section of the House will have a different opinion. This is an amendment which will place politics into a healthy atmosphere and will set an example for us to have a cleaner politics. Therefore, I wholeheartedly support amendment No. 176.

My third small point is with regard to amendment 92 of Shri Humayun Kabir. Here is an example that if we at least decide to nationalise any particular sector we can still co-exist, the control will be of the Government but still the public and the private citizens at large will be able to participate to the extent of nearly 70 per cent. It is an example where I believe Government should have no hesitation in accepting the amendment because they are not affected in any way. I wholeheartedly support this amendment moved by Shri Humayun Kabir.

श्री देवेन सेन : सभापति महोदय, मेरा संशोधन क्लाज़ 3 में इस प्रकार से है :

> "*after* line 42, *add*—
>
> "(7) The Central Government may take over any other bank whose name does not appear in the first schedule, at any time by issuing a notification in the Gazette."

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी बैंकों को ले लिया जाए बल्कि इसके द्वारा सरकार को यह पावर देना चाहता हूँ कि अगर आगे जरूरत पड़े और गवर्नमेंट मुनासिब समझे तो नोटिस इश्यु करके बैंकों को ले सकती है। फिर कोई अध्यादेश जारी करने की जरूरत नही पड़ेगी।

मैं उम्मीद करता हूँ कि ला मिनिस्टर मेरी इस तरमीम को स्वीकार कर लेंगे।

SHRI N. K. SOMANI: Sir, I am speaking on my amendment No 303 with a very brief background. Before the hon. House rushes to pass this Bill of gross and ruthless expropriation of public property, I would like to bring to the notice of the House that when about hundred employees of the Indian Airlines and Air India Corporations saw the Prime Minister she is supposed to have told them that there is no future for democracy in this country as long as banks, industries and newspapers are not nationalised in our own manner and method. I would like to bring this danger to the notice of this House. I would like to quote only two lines which have appeared in the editorial of a paper. Mr. Frank Moraes says in the Indian Express today.

> "It does not call for high courage to raid other people's tills. According to our new monopolists, why bother to create wealth when you can seize it".

If the objective of the Government of India is to provide a new direction to the banks, to what they call economic improvement, and if they are not satisfied with the working of the banks they can very well do it if they accept Shri Kabir's very sensible suggestion. If they are still hesitant to do that on any legal ground then they should be satisfied with just about 51 per cent of the share capital of each bank, because not only are we a mixed economy so far as I am concerned it is the repeated assurance given by the Planning Commission and the Government of India, and to leave a minority in the shape of 49 per cent shareholders which you can distribute in any equitable manner as you like by reconstucting the share holding. It will be immensely preferable and in the interest of sound banking. I would therefore like to appeal that this amendment should be accepted.

श्री बेणीशंकर शर्मा : सभापति महोदय; मैं अपने संशोधन नं० 330 के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूँ। हम सभी लोग भी उन सिद्धान्तों के ही समर्थक हैं जिनसे कि इस देश का हित और कल्याण हो। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यही हमारा सिद्धान्त है। लेकिन जिस ढंग से यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसके हम विरोधी हैं। मुझे कुछ ऐसे सुझाव देने हैं जिनसे कि इस राष्ट्रीयकरण से जो हित सोचा गया है, वह कुछ अंशों में पूरा हो सके। क्लाज़ तीन में कहा गया है कि जितने भी बैंक्स हैं उनका अलग अलग अस्तित्व रखा जायेगा। मैं नहीं समझता कि जब हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं तब फिर इतने सारे बैंकों को अलग अलग रखने की क्या आवश्यकता है। मेरा संशोधन है कि स्टेट बैंक जो पहले से ही एक राष्ट्रीय बैंक है, उसी के साथ सब बैंकों को अमलगमेट कर दिया जाय। क्योंकि आप देखेंगे कि आज जितने भी बैंक हैं, बैंक आफ़ बड़ौदा, बैंक आफ़ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक आदि हर एक की एक-एक शहर में कई कई ब्रान्चें हैं। कलकत्ते में एक एक मोहल्ले में दस-दस शाखायें होने से काफी खर्चा होगा। साथ साथ इतने बैंकों के लिए, मैं जानता हूँ कि जो अभी अधिकारी काम कर रहे हैं वे वहां नहीं रहेंगे, उसके बदले नये अधिकारी रखे जायेंगे, जिनका मिलना कठिन हो जायेगा। लेकिन जहां तक एकराष्ट्रीय बैंक का सवाल है उसके लिए उचित अधिकारी और जो आर्थिक मामले के विशेषज्ञ हों आ सकते हैं। किन्तु इतने बैंकों के लिए आपके भाई भतीजों में उस ढंग के आदमी नहीं मिल सकते। इसलिए मेरा संशोधन है कि इन सब बैंकों का अलग अलग अस्तित्व न कर सब बैंकों को स्टेट बैंक में अमलगमेट कर दिया जाय और फिर स्टेट बैंक शाखायें गांव में, जिस की आबादी 5000 से ज्यादा हो, और शहर में कर दी जायें जिस से किसानों को, छोटे छोटे कारखाने वालों को लाभ पहुंच सके।

SHRI GOVINDA MENON: Three hon. members, Shri Humayun Kabir, Shri Lobo Prabhu and Shri N. K. Somani have suggested that after the banks have been taken over the shares should be given to the members of the public. Shri Lobo Prabhu and Shri Somani have suggested 51 per cent

[Shri Govinda Menon]

and Shri Kabir some other percentage. These are things which can be considered later. There is nothing preventing the Government from doing that. After having got possession of these banks schemes will be framed, regulations and rules will be framed and they will be placed before the House.

SHRI S. S. KOTHARI : Is it not excessive delegation of authority ? Will the Law Minister consider that ?

SHRI GOVINDA MENON : We will consider that. I am thankful to Shri Kothari who thought that I did not know anything about banking. Now he thinks I know at least some law.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Everyone has some weak moments.

SHRI GOVINDA MENON : These are things which can be considered later, because a person possessed of property can transfer it. We have not thought about these details.

One hon. Member spoke about amalgamation. An amendment has been given notice of by Shri P. C. Sethi, amendment No. 130, under which power will be taken for amalgamation etc. But I do not accept the suggestion that this should be a big monolity amalgamated with the State Bank of India.

The amendment of Shri Limaye was that loans should not be given without proper security and all that. You will see that sub-clause (5) of clause 3 states that the corresponding new banks shall carry on banking.

SHRI N. DANDEKER : His point is that no advance, secured or unsecured, shall be given to political parties or politicians.

SHRI GOVINDA MENON : I do not think there is any qualification like "political". His point was that no clean advance shall be made.

SHRI N. DANDEKER : No advance of any kind.

SHRI GOVINDA MENON : He said that no clean advance should be given. Banks will give advance if there is proper credit for the person who seeks the advance. That is the entire scheme of banking in our country and if this is to be amended then we have to amend the Banking Companies Act. So, I oppose all the amendments.

SHRI D. N. PATODIA : What about my amendment about guaranteed depositors' money ?

SHRI GOVINDA MENON : The Deposit Insurance Act will apply to this also. Then, I do not accept the suggestion of the hon. Member that there is any suspician in the minds of the public and the depositors with respect to the security of their deposits. There are already 10 or 12 banks in the public sector and it is a very mischievous suggestion, according to me, to make that there would be any lack of faith on the part of the public.

I request them to withdraw the amendments.........(*Interruption*).

SHRI D. N. PATODIA : You are encouraging withdrawals.

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय मेरे संशोधन को मान नहीं रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN : He has said that he is not accepting your amendment.

SHRI PILOO MODY : He has misrepresented.

MR. CHAIRMAN : That is his right, to represent or to misrepresent.

SHRI PILOO MODY : You should have corrected him on that and insisted that he understood the amendment.

MR. CHAIRMAN : Shri Dandeker corrected the Minister.

SHRI PILOO MODY : No advances.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मंत्री महोदय का दिमाग इतना बन्द है कि उस में कोई चीज घुस हीं नहीं सकती । वह मेरे अमेंडमेंट को भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं ।

SHRI GOVINDA MENON : And yours is all open !

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय दिमाग को खुला रक्खें । इस प्रकार से किवाड़ बन्द न करें, वह मेरे अमेंडमेंट को ठीक तरह से पढ़ें । क्लीन ऐडवान्सेज की बात नहीं है ।

SHRI GOVINDA MENON : That amendment will not fit into the scheme of this clause. Any how, I am not accepting it. Mr. chairman : It is for the Minister to either accept it or reject it. It is his right.

SHRI PILOO MODY : After he has understood it he can rejeet it. It is a very important amendment. Let the whole country know what he is rejecting.

MR. CHAIRMAN : Whether he understood it or did not understand it, is there any amedment which I should put to the vote of the House separately ?

SHRI D.N. PATODIA : Yes, No. 282.

SHRI MADHU LIMAYE : No. 176 also.

SHRI S. K. TAPURIAH: No. 176 also. Let the country know what they are rejecting.

SHRI HUMAYUN KABIR : The Minister has himself said...(*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : There is no scope for any further discussion. Do you want your amendment to be put to the vote of the House ?

SHRI HUMAYUN KABIR : I am not pressing it since the Minister says that they have not given thought to it and that it will be considered later.

SHRI GOVINDA MENON : We will consider it.

MR. CHAIRMAN : Now, I put amendment No. 176 moved by Shri Madhu Limaye to the vote of the House.

The question is :

"Page 2,—

after line 36, *insert*—

"Provided that no advances either secured or unsecured shall be granted to political organisations and individuals for political purposes. (Illustration : Giving of an advance to AICC shall come within this provision." (176).

The Lok Sabha divided :

Division No. 9] **[17. 42 hrs.**

AYES

Abraham, Shri K. M.
Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Banerjee, Shri S. M.
Basu, Shri Jyotirmoy
Bhagaban Das, Shri
Bharati, Shri Maharaj Singh
Brij Bhushan Lal, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Dandeker, Shri N.
Dange, Shri S. A.
Dar, Shri Abdul Ghani
Deb, Shri D. N.
Dwivedy, Shri Surendranath
Esthose, Shri P. P.
Fernandes, Shri George
Gopalan, Shri P.
Gowd, Shri Gadilingana
Guha, Shri Samar
Jena, Shri D.D.
Jha, Shri Bhogendra
Joshi, Shri S. M.
Kachwai, Shri, Hukame Chand
Kalita, Shri Dhireswar
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Kisku, Shri A. K.
Kathari, Shri S. S.
Kripalani, Shri J. B.
Kundu, Shri S.
Kushwah, Shri Yashwant Singh
Limaye, Shri Madhu
Madhukar, Shri K. M.
Majhi, Shri Mahendra
Mangalathumadam, Shri
Meghachandra, Shri M.
Mody, Shri Piloo.
Mohamed Imam, Shri J.
Molahu Prasad, Shri
Naik, Shri R. V.
Nambiar, Shri
Nihal Singh, Shri
Onkar Singh, Shri
Parmar, Shri D. R.
Paswan, Shri Kedar

Patil, Shri N. R.
Patodia, Shri D. N.
Puri, Dr Suraya Prakash
Ramamurti, Shri P.
Saboo, Shri Shri Gopal
Sambhali, Shri Ishaq
Satya Narain Singh, Shri
Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Sheopujan
Shivappa, Shri N
Tapuriah, Shri S K
Tyagi, Shri Om Prakash
Viswambharan, Shri P.
Viswanatham, Shri Tenneti

NOES

Achal Singh, Shri
Agadi, Shri S. A.
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Aga, Shri Ahmad
Ahmed, Shri F. A.
Arumugam, Shri R. S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Bhagat, Shri B R.
Bhagavati, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Birla, Shri R. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Buta Singh, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri D. R.
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J. K.
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri N. T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ering, Shri D.
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C. D.
Ghosh, Shri Bimalkantri
Ghosh, Shri P. K.
Ghosh, Shri Parimal
Govind Das, Dr.
Gupta, Shri Lakhan Lal
Hajarnawis, Shri
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J. N.
Hem Raj, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulsidas
Jadhav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S.C.
Kahandole, Shri Z. M.
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Karan Singh, Dr.
Katham, Shri B. N.
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri M. A.
Kinder Lal, Shri
Kripalani, Shrimati Sucheta
Krishna, Shri M. R.
Krishnan, Shri G. Y.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Mandal, Dr. P.
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Masuriya Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Mehta, Shri P. M.
Melkote, Dr.
Menon, Shri Govinda
Minimata, Shrimati Agam Dass Guru
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mohsin, Shri
Mrityunjay Prasad, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Murti, Shri M. S.
Naghnoor, Shri M. N.
Naidu, Shri Chengalraya
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath

Palchowdhury, Shrimati Ila
Pandey, Shri K. N.
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manubhai
Patil, Shri Deorao
Patil, S.D.
Patil, Shri S.K.
Poonacha, Shri C. M.
Pradhani, Shri K.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Dhani Das, Shri
Ram Sewak, Shri Chowdhary
Ram Swarup, Shri
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri J. Ramapathi
Raut, Shri Bhola
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri Ganga
Reddy, Shrimati Sudha V.
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Saleem, Shri M. Yunus
Sambasivam, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sayeed, Shri P.M.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shah, Shri Shantilal
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Madhoram
Sharma, Shri Naval Kishore
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T.M.
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri S.N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Sinha, Shri Mudrika
Snatak, Shri Nar Deo
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Sursingh Shri
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Ulaka, Shri Ramachandra
Veerappa, Shri Ramachandra
Venkatasubbaiah, Shri P.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. CHAIRMAN : The result* of the division is :

AYES : 61 ; NOES : 173.

The motion was negatived.

SOME HON. MEMBERS : Shame, Shame !

MR. CHAIRMAN : Now, I put amendment No. 282 moved by SHRI D.N. Patodia to the vote of the House. The Lobbies have already been cleared.

The question is :

Page 2, *after* line 36, *insert*—

"(5A) All deposits in the corresponding new banks shall be guaranteed as regards their repayment in full by the Central Government." (282)

The Lok Sabha Divided :

* The following Members also recorded their rootes for AYES :
Sarvashri Ranga and C.C. Desai.

Division No. 10] [17.45 hrs.

AYES

Amat, Shri D.
Amin, Shri R K.
Brij Bhushan Lal, Shri
Dandeker, Shri N.
Deb, Shri D.N.
Desai, Shri C.C.
Diviedy, Shri Surendranath
Fernandes, Shri George
Gowd, Shri Gadilingana
Jena, Shri D.P.
Joshi, Shri S.M.
Kachwal, Shri Hukam Chand
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kothari, Shri S.S.
Kripalain, Shri J.B.
Kushwah, Shri Yashwant Singh
Limaye, Shri Madhu
Majhi, Shri Mahendra
Mody, Shri Piloo
Mohamed Imam, Shri J.
Naik, Shri R.V.
Onkar Singh, Shri
Polodia, Shri D.M.
Ranga, Shri
Saboo, Shri Shri Gopal
Sharma, Shri Beni Shanker
Shivappa, Shri N.
Tapuriah, Shri S.K.
Tyagi, Shri Om Prakash

NOES

Achal Singh, Shri
Ahiwar, Shri Nathu Ram
Aga, Shri Ahmed
Agadi, Shri S.A.
Ahmed, Shri F.A.
Arumugam, Shri R.S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Banerjee, Shri S.M.
Barua, Shri Beda-brata
Barua, Shri, R.
Basu, Dr. Maitrayee
Bhagatis, Shri B.R.
Bhagavati, Shri
Bhandare, Shri R.D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B.N.
Bhattacharyya, Shri C.K.
Birla, Shri R.K.
Bohra, Shri Onkarlal
Buta Singh, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chatterjee, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R.L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri D.R.
Chavan, Shri Y.B.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J.K.
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri N.T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Dhillon, Shri G.S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ering, Shri D.
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh Shri, K.R.
Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C.D.
Ghosh, Shri Bimalkanti
Ghosh, Shri, P.K.
Ghosh, Shri Parimal
Gopalan, Shri P.
Govind Das, Dr.
Gupta, Shri Lakhan Lal
Hajarnawis, Shri
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J.N.
Hem Raj, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V.N.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S C.
Kahandole, Shri Z.M.
Kalita, Shri Dhireswar
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Karan Singh, Dr.
Katham, Shri B N.
Kevade, Shri, B.R.
Kedarai, Shri C.M.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri M.A.
Kinder Lal, Shri
Kripalani, Shrimati Sucheta
Krishna, Shri M. R.
Krishnan, Shri G. Y.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lutfal Haque, Shri
Madhukar, Shri K. M.
Mahadeva Prasad, Dr.
Maharaja, Shri Vikram Chand
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mangalathumadam, Shri

Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Masuriua Din, Shri
Meghachandra, Shri M.
Mehta, Shri Asoka
Mehta, Snri P. M.
Malkote, Dr.
Menon, Shri Govinda
Minimata Agam Das Guru, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. C.
Mohsin, Shri
Mrityunjay Prasad, Shri
Mukherjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Murti, Shri M. S.
Naghnoor, Shri M.N.
Naidu, Shri Chengalraya
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Palchoudhury, Shrimati Ila
Pandey, Shri K. N.
Panigrahi Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Paswan, Shri Kedar
Patel, Shri Manubhai
Patil, Shri Aventrao
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri N. R.
Patil. Shri S. D.
Patil, Shri S. K.
Poonacha, Shri C. M.
Pradhani, Shri K.
Pramanik, Shri J. N.
Puri, Dr. Surya Prakash
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Raghu, Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Dhani Das, Shri
Ram Sewak, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Jagannath
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri J Ramapathi
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri Ganga
Reddy, Shrimati Sudha V.
Rohtagi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Biswanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Saleem, Shri M. Yunus
Sambasivam, Shri
Sambhali, Shri Ishaq
Sankata Prasad, Dr.
Savitri Shyam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shah, Shri Shantilal
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B
Sharma, Shri Madhoram
Sharma, Shri Naval Kishore
Sharma, Shri Yogendra
Shasthi Bhusan, Shri
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Singh, Shri D. N.
Sinha, Shri Madrika
Snatak, Shri Nar Deo
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Ulakka, Shri Ramachandra
Veerappa, Shri Ramachandra
Venkatasubbaiah, Shri P.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yabab, Shri N. P.
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. CHAIRMAN : The result of the division is :

AYES: 29 ; NOS : 191.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall put all the other amendments to clause 3 to the vote of the House.

Amendments Nos. 64, 92, 103, 156, 157, 177, 209. 219, 303, 319 and 330. *were put and negatived.*

MR. CAAIRMAN : The question is :

> "That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.

7.45 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Crisis in Jute Industries

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : Mr. Chairman Sir, This morning at the time of discussion the short notice question some storm was raised over the issue of impending crises in the jute mills. Sir, Jute industry was one of the most important and vital industries so far as West Bengal was concerned and in fact the existence, growth and development of Calcutta have been mainly due to the row of sprawling jute mills with their smoking chimneyes situated on both sides of the river Hooghly. It is also important to the country as a whole as it is the highest foreign exchange earner accounting for 23% of the value of the country's export trade.

sir, it is also one of the biggest employers. It not only employs direct labour to the tune of 2.33,000 and odd persons as against 3.5 million employed earlier but many times more people are engaged in cultivation of raw jute, its processing, transporting and marketing. In fact there are about four million peasent families in West Bengal, Bihar, Orissa Assam and (the jute growing States) who depend for their livelihood on its cultivation. It is also the mainstay for thousands of small middlemen, merchants, stockists, truck-owners, cart-man, coolies and people engaged in assorting, grading and baling of the commodity. Besides thousands of people are employed in inland waterwavs, banking, insurance and many other ancillary industries. As such, even on a modest calculation, more than 20 million people would be depending on this industry for their daily bread. It contributes about Rs. 75 crores per year to the State and Central exchequer by way of excise and export duties and other local taxes besides being once the contributor of the biggest incometax revenue in that region.

You know, Sir, that there has been a dead-lock in the negotiations between the labour and management over the increase of wages and other amenities and the industry is to-day threatened with a strike unprecedented in its annals which is to start on and from the 4th August, 1969. This will be disastrous both for the industry and the labour.

Sir I will appeal to the labour leaders through you not to precipitate this strike in the larger interest of the industry as well as of labour and agriculture till the Bibhuti Mishra Committee which has been set up by the Central Government and the Tariff Commission have gone thoroughly into the whole question of cost structure of the finished goods and other matters incidental thereto. Sir, the demand for increase in wages by the labour is natural and understandable considering the increase in the cost of living.

I may say without any fear of contradiction that the worker in Jute mills in West Bengal is the lowest paid in the whole of the country and his claim deserves sympathetic consideration at all hands.

But there are so many demands on this industry besides the demand of labour which have got to be met. There is the demand of Government in the shape of excise and export duties and of agriculturists in the shape of an adeque price for their raw jute. The support price of jute has been fixed at Rs. 107. per quintal which cannot and should not be disturbed in the interest of our agricu'tural economy. Therefore, the only thing that is capable of regulation is the excise and export duties. Unless and until Government comes to the rescue of this industry and reduces the excise duty and totally abolishes the export duty, there is no hope of salvation for this industry. Sir, I do not hold any brief for the ma-